राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 236 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार,19 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ट्रैक पर उतरे किसान, रोकी गई ट्रेनें

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कृषि कानूनों के खिलाफ गुरूवार को किसानों ने देशभर में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकीं। इस प्रदर्शन का हरियाणा-पंजाब में ज्यादा असर दिखा दोनों राज्यों के कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी ट्रैक पर बैठ गए। इधर, राजस्थान में जयपुर और आस-पास के इलाकों में भी ट्रेनें रोकी गईं। जयपुर में जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन का ज्यादा असर देखा गया। इसके अलावा अलवर, बूंदी, कोटा, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दीं। मप्र में भी कुछ जगह रेलवे स्टेशन और रेल ट्रैक पर प्रदर्शन किया गया। वहीं हरियाणा के खरक पुनिया में बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को एक तरह से खुली धमकी दी है कि केंद्र सरकार को किसी भी तरह कि गलत धारणा नहीं होना चाहिए कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस जाएंगे। टिकैत ने कहा कि अगर वे जोर देते हैं, तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल के साथ-साथ विरोध करेंगे।

सरकार पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि फसलों की कीमतों में इजाफा नहीं हुई है, लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। अगर केंद्र ने स्थिति को बर्बाद कर दिया, तो हम अपने ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल में भी ले जाएंगे। किसानों को वहां भी एमएसपी नहीं मिल रही। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने मोतीनगर के पास ट्रैक जाम कर दिया। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मेट्रो प्रबंधन भी अलर्ट था। एहतियात के तौर पर टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन, पंडित श्रीराम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए।

किसानों के रेल रोकने के ऐलान को देखते हुए देशभर में रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 एक्स्ट्रा कंपनियां यानी करीब 20 हजार अतिरिक्त जवान तैनात किए थे। इनमें से ज्यादातर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया।

किसान इस बात पर अड़े हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। भारतीय किसान यूनियन (हरियाणा) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंढूनी ने एक बार फिर कहा है कि उनका संगठन किसानों के हितों के लिए लड़ रहा है और नए कृषि कानूनों की वापसी तक वे अपने घरों को नहीं लौटेंगे। चंढूनी ने कहा कि देशभर में पंचायत और महापंचायत जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि केंद्र सरकार आम लोगों की नहीं बल्कि कॉरपोरेट्स की है।

जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी। जगतपुरा स्टेशन पर भी प्रदर्शन किया गया। जयपुर जिले के चौमूं रेलवे स्टेशन पर आंदोलकारी पटरियों पर बैठ गए। उधर अलवर में भी ट्रेनें रोकी गई हैं। प्रदेश के 6 जिलों में रेल रोको प्रदर्शन का असर देखा गया।

पानीपत में टीडीआई सिटी के पास पुल के नीचे वाले ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। वहां किसान ट्रैक पर बैठ गए। करीब 12.45 बजे पहुंची बांद्रा-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। इससे पहले बठिंडा एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट आई थी और पैसेंजर्स को लेने के लिए सिर्फ 2 मिनट रुकी थी। हरियाणा में करीब 80 जगहों पर प्रदर्शन हुए।

यहां 15 जिलों में 21 जगहों पर किसानों ने ट्रेनें रोकीं। पटियाला जिले में नाभा, संगरूर में सुनाम, मानसा, बरनाला, बठिंडा में रामपुरा, मंडी, संगत और गोनियाना, फरीदकोट में कोटकपूरा, मुक्तसर में गिद्दड़बाहा, फाजिल्का में अबोहर और जलालाबाद, मोगा में अजीतवाल, जालंधर में तरनतारन, अमृतसर में फतेहगढ़ में ट्रेनें रोकी गईं।

देशभर के साथ ही मध्यप्रदेश में किसानों का रेल रोको आंदोलन का असर देखा गया। कृषि बिल के विरोध में रीवा, बीना और ग्वालियर में भी ट्रेनें रोकने का प्रयास किया गया। विंध्य क्षेत्र के रीवा, सिंगरौली और बरगवां रेलवे स्टेशन पर भी कांग्रेस और किसान नेता रेलवे ट्रैक तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जा पाए। इधर, भिंड जिले से खबर है कि कृषि बिल के विरोध में भिंड के रेलवे ट्रैक पर भी किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान चंबल घाटी के जननायक का बैनर लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। वे काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर खड़े रहे। इस दौरान राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

किसानों के प्रदर्शन में राजनीतिक दल भी शामिल हुए। पटना में जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के कार्यकर्ताओं ने तय समय (दोपहर 12 बजे) से आधे घंटे पहले ही रेल रोकना शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्ता पटरी पर लेट गए, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

असम को नजरअंदाज करने की ऐतिहासिक गलती सुधार रही है सरकार : प्रधानमंत्री

गुवाहाटी, (एजेंसी)। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को असम को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी और कहा कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर के इस राज्य को नजरअंदाज करने की ऐतिहासिक गलती को ना सिर्फ सुधार रही है, बल्कि तेज गति से उसके विकास के लिए प्रतिबद्ध भी है। इस अवसर पर मोदी ने यह भी कहा कि बीते वर्षों में केंद्र और असम की डबल इंजन सरकार ने इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को कम करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, गुलामी के कालखंड में भी असम देश के सम्पन्न और अधिक राजस्व देने वाले राज्यों में से था। संपर्क का जाल असम की समृद्धि का बड़ा कारण था। आजादी के बाद इस अवसंरचना को आधुनिक बनाना जरूरी था, लेकिन इन्हें अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इतिहास में की गई गलतियों को सुधारने की शुरूआत की थी, अब उनका ना सिर्फ विस्तार किया जा रहा है बल्कि उन्हें और गति दी जा रही है। उन्होंने कहा, यह अब हमारी प्राथमिकता में भी है और इसके लिए सरकार दिन रात एक कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम की वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में राज्य के विकास को नयी ऊंचाई दी और ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि लोगों ने भाजपा की सरकार चुनी। उन्होंने कहा, वर्ष 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ कर दिखाया। आपके वोट की ताकत अभी असम को और ऊंचाई पर ले कर जाने वाली है। असम में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर महाबाहु- ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का लोकार्पण किया, धुबरी-फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। महाबाहु-ब्रह्मपुत्र के शुभारंभ के साथ प्रधानमंत्री ने नीमाटी-माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी-दक्षिण गुवाहाटी और धुबरी-हाटसिंगिमारी के बीच रो-पैक्स पोत संचालन का उद्घाटन किया। नीमाटी और माजुली के बीच रो-पैक्स परिचालन से वर्तमान में वाहनों द्वारा तय की जा रही 420 किलोमीटर की कुल दूरी कम होकर केवल 12 किलोमीटर रह जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रह्मपुत्र और बराक सहित असम को अनेक नदियों की जो सौगात मिली है, उसे समृद्ध करने के लिए आज महाबाहु-ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, ये कार्यक्रम ब्रह्मपुत्र के जल से इस पूरे क्षेत्र में जल संपर्क को सशक्त करेगा। उन्होंने जोगीघोपा में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) टर्मिनल का शिलान्यास और ब्रह्मपुत्र नदी पर विभिन्न पर्यटक सुविधाओं और व्यापार की सुगमता के लिए डिजिटल समाधान का शुभारंभ भी किया। धुबरी (उत्तरी तट) और फूलबाड़ी (दक्षिण तट) के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर चार लेन के प्रस्तावित पुलराष्ट्रीय राजमार्ग-127बी पर स्थित होगा। यह असम में धुबरी को मेघालय के फूलबाड़ी, तूरा, रोंग्राम और रोंगजेंग से जोड़ेगा।

भाजपा में पार्टी ही परिवार : नड्डा

धर्मशाला, (एजेंसी)। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित कर कहा कि हम जो लोग भी भाजपा में आए हैं, वहां सभी खुशनसीब हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तक सभी राजनीतिक दल परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। लेकिन भाजपा में पार्टी ही परिवार है। कोई दूसरी पार्टी में 18 करोड़ सदस्य बनाने की ताकत ही नहीं है। दूर-दूर तक किसी के पहुंचने की ताकत नहीं है और यह सभी लोगों के प्रयास की वजह से हुआ है।

जेपी नड्डा ने भाजपा सरकार की योजनाओं का भी जिक्र कर अंत्योदय योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास किया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना जाति के आधार पर नहीं दी गई बल्कि सबके लिए थी। उन्होंने कहा कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमें आगे बढ़ाना है।वहां हमारा उद्देश्य है जिसके साथ हम जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सभी योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से प्रेरित हैं। यही हमारा आर्थिक मॉडल रहा है।

नड्डा ने बताया कि कोरोना के दौरान जब सभी राजनीतिक पार्टियां लॉकडाउन हो गई थीं, उस समय भाजपा कार्यकर्ता सेवाभाव में लगे रहें। 25 करोड़ गरीबों, असहायों को फूड पैकेट्स बांटे गए, लगभग 6 करोड़ लोगों को महीने भर का राशन वितरित हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा का संस्कार केंद्र होता है कार्यालय, इसकारण हर जिले में कार्यालय बनें इस बात को लेकर हम चले हैं। हिमाचल में कई जिलों में नए कार्यालयों का शिलान्यास हो चुका है।

उन्होंने कहा कि हम वोकल फॉल लोकल को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हिमाचल के लॉकल उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें भी हर जिले में अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत में 82 लाख से अधिक कोरोना टीकाकरण हो गया है। मेक इन इंडिया कोविड वैक्सीन को दुनिया भर के सभी देश खरीदना चाह रहे हैं। भारत 16 देशों को कोरोना वैक्सीन भेज रहा है। भाजपा की हिमाचल प्रदेश कार्यसमिति बैठक में जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उपाध्यक्ष सुजान सिंह, अविनाश राय खन्ना सहित कई अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया।

कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर: स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के मामले में अमेरिका और इंग्लैंड के बाद भारत, दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। मंत्रालय ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह आठ बजे तक देश भर में 94 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है।

उसने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के दर में भी पिछले सात दिनों में लगातार कमी आयी है। एक फरवरी को यह 1.89 प्रतिशत थी जो गिर कर बृहस्पतिवार को 1.69 प्रतिशत रह गई। प्रांतों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 18 फरवरी को सुबह आठ बजे तक 1,99,305 टीकाकरण सत्रों में टीके की कुल 94,22,228 खुराक के इंजेक्शन लाभार्थियों को लगाये गये हैं।

इनमें 61,96,641 स्वास्थ्यकर्मी (पहली खुराक), 3,69,167 स्वास्थ्यकर्मी (दूसरी खुराक) और 28,56,420 कोरोना योद्धा (पहली खुराक) शामिल हैं। देश में 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण अभियान के 28 दिन पूरे होने के बाद 13 फरवरी से उन लोगों को टीके की दूसरी खुराक का इंजेक्शन लगना शुरू हो गया है जिन्होंने कम से कम 28 दिन पहले पहली खुराक ली थी। कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण दो फरवरी से शुरू हुआ। टीकाकरण के 33वें दिन (18 फरवरी) को 7,932 सत्रों में टीके के 4,22,998 खुराक के इंजेक्शन लगाए गए। इनमें से 3,30,208 लोगों को पहली खुराक जबकि 92,790 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। मंत्रालय ने बताया कि टीके की दूसरी खुराक लेने वालों में से 58.20 प्रतिशत लोग सात राज्यों से हैं। अकेले कर्नाटक में 14.74 प्रतिशत (54,397 खुराक) इंजेक्शन लगे हैं। मंत्रालय ने बताया कि बृहस्पतिवार तक करीब 1.06 करोड़ (1,06,56,845) लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं।

हिम्मत है तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं अमित शाहः ममता बनर्जी

कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। गुरुवार को शाह और ममता एक ही जिले में अलग-अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शाह जिस वक्त दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में थे, उस वक्त पैलान इलाके में अभिषेक के साथ सभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा-केंद्र के एक मंत्री गंगासागर जाकर बुआ-भतीजे की बात कर रहे हैं। आज मैं कहती हूं कि पहले भतीजे से लड़ो, फिर दीदी से लड़ना। ममता ने सवाल किया-अमित शाह का बेटा भी मेरा भतीजा है। वो बीसीसीआइ का सचिव कैसे बना?

मुख्यमंत्री ने श्रम राज्यमंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि साजिश के तहत जाकिर हुसैन पर हमला किया गया। इसके पीछे विरोधी दल का हाथ है। जनसभा से पहले ममता अपने मंत्री को देखने कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल गई थीं। उन्होंने कहा-विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को डराने की कोशिश हो रही है। जाकिर हुसैन पर हमला किया गया। रेलवे स्टेशन पर हुए हमले में 26 लोग घायल हुए हैं। जाकिर आज जिंदगी और मौत के बीच बेड पर पड़े हुए हैं। उनकी हालत गंभीर है। ममता ने कहा-चक्रवात एम्फन में बहुत से लोग मारे गए लेकिन केंद्र ने बचाव व राहत कार्य के लिए एक पैसा नहीं दिया।

वहीं, सांसद अभिषेक ने कहा कि ममता सरकार ने पिछले 10 वर्षों में राज्य में जो विकास कार्य किए हैं, वैसा किसी राज्य की सरकार ने नहीं किया। भाजपा कह रही है कि भाजपा ने सात वर्षों में बंगाल को तीन लाख करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि वह इस दौरान बंगाल से 75 हजार करोड़ का टैक्स काटकर ले गई है और उसी रुपये से सांसद व विधायक खरीद रही है।

वह तृणमूल के नेता खरीदकर सोनार बांग्ला गढ़ने की बात कर रही है। अभिषेक ने कहा कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने पर वे खुद ही सूली से लटक जाएंगे। इसके लिए सीबीआइ व ईडी को जांच में लगाने की जरुरत नहीं है।

बंगाल में अमित शाह के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, जमकर लगे जय श्रीराम के नारे

कोलकाता। बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दो दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शाह ने शाम में जिले के काकद्वीप इलाके में एक रोड शो भी किया। इस रोड शो में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व आम लोगों ने जमकर जय श्रीराम के नारे लगाए। इस दौरान खुद शाह ने भी जय श्रीराम के नारे लगाए। रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने तृणमूल सरकार पर ''कट मनी संस्कृति'' शुरू करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की लड़ाई इसे खत्म करने की है और यदि पार्टी सत्ता में आई तो राज्य को विकास के मार्ग पर ले जाएगी। शाह ने कहा कि भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' मुख्यमंत्री, विधायक या मंत्री को बदलने के लिए नहीं बल्कि घुसपैठ को बंद करने तथा बंगाल को एक विकसित राज्य में परिवर्तित करने की है। शाह ने इससे पहले काकद्वीप में एक जनसभा को भी संबोधित किया और उन्होंने भाजपा के पांचवें चरण की परिवर्तन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को गंगासागर स्थित कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप के नामखाना में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा के पांचवें चरण की परिवर्तन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद शाह यहां के नारायणपुर गांव में शरणार्थी परिवार सुब्रत विश्वास के घर पहुंचे जहां उन्होंने दोपहर का भोजन किया। शाह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय, राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, राहुल सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने भी जमीन पर बैठकर भोजन किया।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में शुरू जांच प्रक्रिया बंद कर दी

नई दिल्ली, (संवाददाता)। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को कथित यौन उत्पीड़न मामले में फंसाने के षड्यंत्र की जांच के लिए स्वतः संज्ञान के आधार पर शुरू जांच प्रक्रिया बंद कर दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की साजिश को जस्टिस गोगोई के फैसलों से जोड़ा जा सकता है, जिसमें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन(एनआरसी) पर उनके विचार भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्व न्यायमूर्ति एके पटनायक की रिपोर्ट पर आधारित है, जिन्हें न्यायमूर्ति गोगोई के खिलाफ आरोपों में एक बड़ी साजिश की जांच करने का काम सौंपा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट में पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ साजिश को स्वीकार किया गया है,इस खारिज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को दो साल गुजर चुके हैं। गोगोई को फंसाने के षड्यंत्र की जांच में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावना बहुत ही कम रह गई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों के पीछे साजिश होने का दावा किया था।

गौरतलब है कि साल 2019 में एक महिला ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच कराने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि आरोप बेहद गंभीर हैं। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। अगर हमने हमारी आंखें बंद कर ली,तब देश का भरोसा उठ जाएगा। इसके बाद जस्टिस पटनायक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

उपराष्ट्रपति, श्री एम.वेंकैया नायडू हैदराबाद में मावरिक मसीहा - ए पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ़ एन टी. रामाराव पुस्तक का विमोचन करते हुए।

इराक चुनाव में संयुक्त राष्ट्र से पर्यवेक्षण के अनुरोध का भारत ने किया समर्थन

जेनेवा, (एजेंसी)। भारत ने अक्टूबर में इराक में संसदीय चुनाव कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र से पर्यवेक्षण के अनुरोध का समर्थन करते हुए कहा कि वह खाड़ी देश की संप्रभुता का सम्मान करने वाली और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने वाली किसी भी पहल का अनुमोदन करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने इराक के हालात विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि अक्टूबर 2021 में इराक में संसदीय चुनाव देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का मौका होगा।

उन्होंने कहा कि हिंसामुक्त माहौल में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी के साथ पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव से नई सरकार को सुधार लागू करने, जवाबदेही बढ़ाने, इराक के लोगों की वास्तविक आकांक्षा को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे समावेशी और सुलह-सफाई प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा। तिरुमूर्ति ने कहा कि इराक के निर्वाचन आयोग और चुनाव प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण को अंतरराष्ट्रीय मदद से इन चुनावों की विश्वसनीयता कायम होगी और इराक के लोगों के बीच नतीजों को लेकर विश्वास बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत, इराक में आगामी चुनाव के लिए संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण के आग्रह का समर्थन करता है। हम इराक की संप्रभुता, लोकतांत्रिक कवायद को मजबूत करते हुए लोगों के लिए स्वीकार्य विश्वसनीय नतीजों वाली किसी भी प्रकिया का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कवायद लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने की तर्ज पर है और भारत ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर तथा चुनावी प्रेक्षक भेजकर इराक में लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया में अपना योगदान दिया है।

इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि और इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की प्रमुख जियनीन हेनिस प्लासखात ने परिषद को बताया कि इराक में विश्वसनीय चुनाव के लिए जरूरी है कि सभी दल और उम्मीदवारों को मुक्त और सुरक्षित माहौल मिले। उन्होंने उल्लेख किया कि चुनावी पर्यवेक्षण के लिए इराक की सरकार से मिला अनुरोध अभी सुरक्षा परिषद में विचाराधीन है।

ब्लॉगर राय की हत्या मामले में पांच लोगों को मौत की सजा

ढाका, (एजेंसी)। बांग्लादेश में आतंकवाद रोधी एक विशेष अदालत ने जाने माने बांग्लादेशी-अमेरिकी ब्लॉगर अविजीत रॉय की 2015 में हुई हत्या के मामले में सेना के एक भगोड़े मेजर समेत प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी समूह के पांच लोगों को मृत्युदंड सुनाया और एक अन्य व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बांग्लादेश में जन्मे 42 वर्षीय अमेरिकी नागरिक रॉय की इस्लामी आतंकवादियों ने उस समय हत्या कर दी थी, जब वह 26 फरवरी, 2015 को ढाका विश्वविद्यालय में एक पुस्तक मेले से निकले थे। इस हमले में उनकी पत्नी राफिदा अहमद भी घायल हो गई थीं। रॉय धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे।

जानकारी के मुताबिक ढाका की आतंकवाद रोधी विशेष अदालत के न्यायाधीश मोजिबुर रहमान ने सेना के भगोड़े मेजर सैयद जियाउल हक समेत पांच आतंकवादियों को रॉय की हत्या के मामले में मृत्युदंड सुनाया। हक के अलावा मोहम्मद मोज्जम्मल हुसैन उर्फ सैमोन उर्फ शहरियार, मोहम्मद अबु सिद्दिक सोहेल उर्फ साकिब उर्फ साजिद उर्फ शाहाब, मोहम्मद अराफात रहमान और अकरम हुसैन उर्फ अबीर को भी मृत्युदंड दिया गया। अबीर भी इस समय फरार है। न्यायाधीश ने इन आरोपियों पर पचास-पचास-हजार का जुमार्ना भी लगाया। न्यायाधीश रहमान ने इससे करीब एक ही सप्ताह पहले रॉय के प्रकाशक फैसल अरेफिन दिपोन की हत्या के मामले में निष्कासित मेजर हक समेत आठ इस्लामी आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई थी।

इंडोनेशिया के जावा में हुए भूस्खलन के बाद राहत व बचाव काम में लगे आपदा राहत दल के सदस्य।

विएना के स्कोनबर्न पैलेस के एक बगीचे में घूमते हुए लोग।

रॉकेट में ट्रैवल करने की जगह खसरे के टीके पर अपना पैसा खर्च करुंगा : बिल गेट्स

वाशिंगटन, (एजेंसी)। बिल गेट्स ने वैश्विक महामारी का अनुमान लगाया था, अब वहां जलवायु आपदा का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन इस बार वहां बता रहे हैं, कि जलवायु आपदा से कैसे निपटा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, बिजनेस मैगनेट गेट्स की नई किताब पब्लिश हुई है। किताब के लांच के बाद इंटरव्यू में गेट्स ने कहा कि टेस्ला और स्पेस एक्स के बॉस एलन मस्क की तरह वहां मंगल ग्रह की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते हैं। उनकी नजर धरती पर आने वाली समस्याओं पर है। गेट्स ने कहा, यह कहना महत्वपूर्ण है, कि एलन ने टेस्ला के माध्यम से जो किया वहां जलवायु परिवर्तन को लेकर किसी व्यक्ति द्वारा किया सबसे बड़ा योगदान है। और आप भी जानते है कि एलन मस्क कमतर आंकना एक अच्छा आइडिया नहीं है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि मस्क के सॉल्युशन को वहां वास्तिविक सॉल्युशन के रूप में नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि वहां मंगल के बारे में सोचने वाले व्यक्ति नहीं है। गेट्स मानते हैं कि रॉकेट ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि टेस्ला जैसी कंपनियां पैसेंजर्स कारों जैसे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन हमें जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़े बदलाव के लिए अन्य इंडस्ट्रीज की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। गेट्स बताते हैं कि वहां स्पेस में किसी रॉकेट में ट्रैवल करने की जगह खसरे के टीके पर अपना पैसा खर्च करना पंसद करुंगा। उन्होंने कहा, मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करूंगा क्योंकि मेरी संस्था 1,000 डॉलर में खसरे का टीका खरीदकर जिंदगियां बचा सकेगी। मैं कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचता हूं। मैं उस 1,000 डॉलर को खसरे के टीके के लिए इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। बिल गेट्स ने बताया कि उन्होंने कैसे जलवायु परिवर्तन को लेकर काम किया है। दो प्रमुख कारणों की वजह से उनका ध्यान इस ओर गया। पहला यह कि साइंस की तरफ उनका झुकाव हमेशा से ही रहा है और दूसरा यह कि वैश्विक विकास को लेकर दुनिया के सामने क्या चुनौतियों को समझना रहा। बीते कुछ दशक में गेट्स का ध्यान दुनिया के कुछ रिमोट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता कराना रहा है।

टूलकिट मामला: ब्रिटिश सांसद को भारतीय उच्चायोग ने लिखा खुला पत्र

लंदन, (एजेंसी)। भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई आवाजें उठी हैं। इनमें से एक हैं ब्रिटिश सांसद क्लॉडिया वेब, जिन्हें लेकर लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक खुला पत्र लिखा है। वेब ने टूलकिट मामले में भारत में गिरफ्तार किए गए कार्यकताओं की रिहाई की हाल में सोशल मीडिया के जरिए मांग की थी। भारतीय मिशन ने लिखे एक खुले पत्र में वेब्ब से कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के ब्रिटिश नागरिकों की ओर से कोई भी आपत्ति सीधे उच्चायोग के सामने उठाएं। पत्र में कहा गया है कि हमने हाल के भारतीय कृषि कानूनों के संबंध में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए विस्तृत और समग्र स्पष्टीकरण दिया है। इस कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान समुदाय का एक छोटा सा समूह प्रदर्शन कर रहा है।

क्लॉडिया वेब्ब पूर्वी इंग्लैंड में एक अहम ब्रिटिश भारतीय निर्वाचन क्षेत्र लीसेस्टर ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाली सांसद और विपक्षी लेबर पार्टी की सदस्य हैं। उन्होंने भारत में विरोध प्रदर्शनों को लेकर ब्रिटेन की सरकार के बयान जारी किए जाने की अपील करने वाली ई-याचिका को समर्थन दिया है। इस याचिका पर एक लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। क्लॉडिया ने दिशा रवि और नोदीप कौर के समर्थन में ट्वीट किया था। किसी भी याचिका पर हाउस ऑफ कॉमन्स के वेस्टमिंस्टर हॉल में बहस के लिए कम से कम एक लाख हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है। इस मामले में हाल में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है और वकील निकिता जैकब एवं इंजीनियर शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

गुरुदेव टैगोर के ह्यूस्टन आने के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम हुआ

ह्यूस्टन, (एजेंसी)। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के फरवरी 1921 में ह्यूस्टन आने के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर टैगोर ग्रोव स्मारक पर कड़कड़ाती सर्दी के बीच कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी क्रम में गुरुदेव के संगीत और उनकी कविताओं का ऑनलाइन पाठ भी किया गया। टैगोर सोसाइटी ऑफ ह्यूस्टन (टीएसएच) द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में ह्यूस्टन के महावाणिज्यदूत असीम महाजन, कुछ आमंत्रित अतिथियों और टीएसएच के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। टैगोर ग्रोव मेमोरियल में टैगोर की कांस्य प्रतिमा है, जिसका अनावरण 2013 में एनर्जी कॉरिडोर स्थित रे मिलर पार्क में किया गया था। यह गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगौर की छठी ऐसी आदमकद प्रतिमा है जो उनके जन्म स्थान कोलकाता से बाहर लगी हैं और अमेरिका में यह पहली ऐसी प्रतिमा है।

टीएसएच के अध्यक्ष गोपेंदु चक्रवर्ती के नेतृत्व में संस्था ने अतिथियों का स्वागत किया और टैगोर के सार्वभौमिकता और विश्व शांति के संदेश को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अपने दूसरे अंतर महाद्वीपीय व्याख्यान दौरे में राइस विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए टैगोर ने एक सदी पहले ह्यूस्टन की यात्रा की थी। इसकी याद में कार्यक्रम आयोजित करना बेहद अच्छा है। इसने पूरे अमेरिका में उनके साहित्यिक और अन्य कार्यों में काफी रुचि पैदा की। महाजन ने टैगोर के सीमारहित दुनिया के संदेश को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संबंधों और लोगों के बीच संपर्क गहरा करने के लिए वाणिज्य दूतावास मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित है। टैगोर ग्रोव सार्वभौमिक शांति और प्रेम के प्रतीक के रूप में शहर में सभी समुदायों के लिए समर्पित है। ग्रोव जनता के लिए खोला जाएगा और टीएसएच लोगों के यहां आने और टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का स्वागत करता है। टैगोर पर व्याख्यान देने वाली श्रेया गुहाठाकुरता और वक्ता ब्रातती बंदोपाध्याय ने रविवार को टैगोर की रचनाओं का पाठ किया था।

इक्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति गुस्तावो नोबोआ का निधन

क्वीटो, (एजेंसी)। इक्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति गुस्तावो नोबोआ का अमेरिका में ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो ने ट्वीट कर नोबोआ के निधन की पुष्टि की है। उन्होंने नोबोआ को देशभक्त बताते हुए कहा कि उनके निधन से इक्वाडोर शोक में है। वह पूर्व राष्ट्रपति की याद में कल से राजकीय शोक घोषित करेंगे। तत्कालीन राष्ट्रपति जामिल माहुद के खिलाफ विद्रोह और इसकी वजह से माहुद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नोबोआ जनवरी, 2000 में राष्ट्रपति बने थे। उस समय देश गंभीर आर्थिक संकटों का सामना कर रहा था और इस संकट की वजह से सरकार ने अमेरिकी डॉलर को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपना लिया। देश में वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थीं और आधे से ज्यादा बैंक या तो बंद हो गए या उनमें ठीक से कामकाज नहीं हो रहा था। नोबोआ के बाद लुसियो गुतेरेज देश के राष्ट्रपति बने। नोबोआ ने मुद्रा में बदलाव किया और अल नीनो जैसी गंभीर पर्यावरण की स्थिति से निपटते हुए इक्वाडोर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना शुरू किया।

ढांचागत सुधार के लिए आईएमएफ से 50 करोड़ डालर का कर्ज लेगा पाकिस्तान

इस्लामाबाद, (एजेंसी)। नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके सत्ता में आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जैसे तय कर लिया है कि वह पाकिस्तान को कर्ज में डूबोकर ही मानेंगे। सत्ता में आने से पहले इमरान ने वादा किया था कि वह विदेशी संस्थाओं से कर्ज लेने की संस्कृति पर रोक लगाएंगे, लेकिन अब वह खुद ही कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं। ताजा मामला अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, जिससे पाकिस्तान 50 करोड़ डॉलर कर्ज लेने जा रहा है।

वह भी तब जब हर पाकिस्तानी नागरिक पर अब 1 लाख 75 हजार रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान सरकार और आईएमएफ के बीच मंगलवार को सुधारों को लेकर एक समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद अब पाकिस्तान को आईएमएफ से 50 करोड़ डॉलर कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि अर्थव्यवस्था को मदद दी जाएगी और ढांचागत सुधार किए जाएंगे। वित्त मंत्री अब्दुल हाफजि शेख ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है।

पाकिस्तान यह कर्ज ऐसे समय पर ले रहा है जब हाल में ही पाकिस्तान की संसद में इमरान खान सरकार ने कबूल किया है कि अब हर पाकिस्तानी के ऊपर अब एक लाख 75 हजार रुपए का कर्ज है। इसमें इमरान खान की सरकार का योगदान 54901 रुपए है, जो कर्ज की कुल राशि का 46 फीसदी है। कर्ज का यह बोझ पाकिस्तानियों के ऊपर पिछले दो साल में बढ़ा है। यानी जब इमरान ने पाकिस्तान की सत्ता संभाली थी तब देश के हर नागरिक के ऊपर 120099 रुपए का कर्ज था। वित्त वर्ष 2020-21 के राजकोषीय नीति पर बयान देते हुए पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने माना है कि इमरान खान सरकार राजकोषीय घाटे को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के चार फीसदी तक करने में विफल रही है। इस तरह सरकार ने 2005 की राजकोषीय जिम्मेदारी और ऋण सीमा (एफआरडीएल) अधिनियम का उल्लंघन किया है। ऐसे में पाकिस्तान का कुल रोजकोषीय घाटा जीडीपी का 8.6 फीसदी रहा है, जो एफआरडीएल अधिनियम कानून की सीमा से दोगुने से भी अधिक है। पाकिस्तान ने देश के ऊपर बढ़ते विदेशी कर्ज से निपटने के लिए की राजकोषीय जिम्मेदारी और ऋण सीमा (एफआरडीएल) अधिनियम को साल 2005 में पारित किया था। इसमें प्रावधान किया गया था कि राजकोषीय घाटा देश की अर्थव्यवस्था से चार फीसदी से ज्यादा न हो। इसमें यह भी कहा गया था कि राजकोष को लेकर सरकार की सभी नीतियों को गहराई से अध्ययन भी किया जाए।

पाकिस्तान की संसद में यह रिपोर्ट गुरुवार को पेश की गई थी। पाकिस्तान के इतिहास में इस रिपोर्ट को सबसे कम जानकारी वाला नीतिगत बयान बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि ऋण नीति कार्यालय ने वित्त मंत्रालय को नीति का एक विस्तृत मसौदा पेश किया था। हालांकि, उन्हें आदेश दिया गया कि इस रिपोर्ट को शीर्षक सहित केवल 11 पन्नों में ही समेटा जाए।

दो वर्षों के राजकोषीय नीति विवरण में बताया गया है कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार के कार्यकाल के दौरान लोगों के ऊपर 54,901 रुपए का कर्ज बढ़ा है। जून 2018 में पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक ऋण 120,099 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था। इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार के पहले साल कर्ज की यह राशि 28 फीसदी बढ़कर 33,590 ट्रिलियन रुपए हो गई, जबकि उसके अगले साल यह कर्ज 14 फीसदी और बढ़ गया।

उत्सुल मुस्लिमों के उत्पीड़न में जुटा चीन, मस्जिदों पर लाउडस्पीकर प्रतिबंधित, अरबी भाषा पर लगाई रोक

सान्या, (एजेंसी)। उइगर मुस्लिमों पर कहर ढाने वाला चीन अब उत्सुल मुस्लिमों की पहचान को खत्म करने में जुट गया है। दक्षिण चीन सागर से सटे चीन के सान्या शहर में रहने वाले 10 हजार उत्सुल मुस्लिमों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दमन की सारी हदें पार कर दी हैं। उत्सुल मुस्लिमों को मस्जिदों पर लाउडस्पीकर नहीं लगाने दिया जा रहा है। नई मस्जिदों का निर्माण रोक दिया गया है। इसके साथ ही अरबी पढ़ने पर बैन लगा दिया गया है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी कोशिश है कि उत्सुल मुस्लिमों की धार्मिक पहचान खत्म हो जाए और वे चीनी लाल रंग में रंग जाएं। हैनान द्वीप पर बसे इस शहर में कम्युनिस्ट पार्टी ने विदेशी प्रभाव और धर्मों के खिलाफ एक मुहिम सी चला रखी है। स्थानीय धार्मिक नेताओं ने बताया कि इससे पहले चीनी प्रशासन उत्सुल मुस्लिमों को उनकी पहचान बनाए रखने का समर्थन करता था, लेकिन शी जनिपिंग की सरकार आने के बाद अब उत्सुल मुस्लिमों की पहचान को खत्म करने की मुहिम शुरू हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी की अब कोशिश है कि पूरे चीन में एक ही संस्कृति हो और सभी उसे मानें।

उधर, कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि चीन में मुस्लिम समुदाय पर लगाई गई पाबंदियों का उद्देश्य हिंसात्मक धार्मिक अतिवाद पर काबू पाना है। चीनी प्रशासन ने उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अपने अभियान को इसी आधार पर न्यायोचित ठहराया है। अमेरिका के मेरीलैंड में चीन के मुस्लिमों के विशेषज्ञ प्रफेसर मा हैयून कहते हैं उत्सुल मुस्लिमों पर कड़ा नियंत्रण स्थानीय समुदायों के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वास्तविक चेहरे को उजागर करता है।

एक साल बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई किम की पत्नी जू

प्योंगयांग, (एजेंसी)। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की पत्नी रि सोल जू बीते एक साल में पहली बार बुधवार को मीडिया के सामने नजर आईं। वह अपने पति किम जोंग उन के साथ एक कंसर्ट में भाग लेने पहुंची थीं। उत्तर कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी के अखबार ने किम जोंग उन और उनकी पत्नी की तस्वीरें प्रकाशित की हैं। यह कंसर्ट किम जोंग उन के दिवंगत पिता और देश के पूर्व शासक किम जोंग इल की जयंती पर आयोजित किया गया था।

रि सोल जू अकसर अपने पति के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आती रही हैं, लेकिन बीते साल जनवरी के बाद से वह नहीं दिखी। अखबार के मुताबिक उन्होंने प्रेगनेंसी की अफवाहों को गलत करार दिया है। एक साल से रि सोल जू के सार्वजनिक स्थलों पर नजर न आने को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वह प्रेगनेंट हैं या फिर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस बीच दक्षिण कोरिया की एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने मंगलवार को बताया था कि रि सोल जू बीते एक साल से कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए घर से बाहर नहीं निकली हैं।

नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने बताया कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपने तीन बच्चों के साथ घर पर ही रह रही हैं। किम जोंग उन के तीन बच्चे हैं लेकिन इन बच्चों के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। यही नहीं उनकी तस्वीरें भी नहीं देखी गई हैं। उत्तर कोरिया ने अब तक कोरोना के मामलों की कोई पुष्टि नहीं की है। हालांकि दक्षिण कोरियाई एजेंसी का कहना है कि उत्तर कोरिया में कोरोना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि उत्तर कोरिया का चीन से करीबी संबंध है और पहली बार कोरोना संक्रमण चीन में ही सामने आया था।

उत्तर कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में आयोजित कंसर्ट में रि सोल जू और किम जोंग उन मुस्कुराते नजर आए। तस्वीरों में कोई भी मास्क नहीं लगाए हुए था और न ही कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिखा। यही नहीं इस दौरान किम जोंग उन अपने दिवंगत पिता और दादा की समाधि पर भी गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। किम जोंग उन के पिता की जयंती को उत्तर कोरिया में काफी धूमधाम से मनाया जाता है।

हंगरी के बुडापेस्ट शहर में चीन से खरीदे गये सिनोफार्म कोविड-19 टीके को सौंपते हुए कर्मचारी।

दिशा रवि की हाई कोर्ट में याचिका, निजी चैट लीक न करे दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली। टूलकिट मामले में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जांच से जुड़ी जानकारी, उनके निजी चैट किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध न कराने के संबंध में दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की है। अधिवक्ता अभिनय शेखरी, संजना श्रीकुमार, वृंदा भंडारी के माध्यम से दायर याचिका में दिशा ने कहा है कि जांच से जुड़ी जानकारी मीडिया में लीक न करने के संबंध में पुलिस को निर्देश दिया जाए। साथ ही मीडिया को उनके निजी चैट प्रकाशित करने से भी रोका जाए। बता दें कि मंगलवार को दिशा के आवेदन पर निचली अदालत ने उन्हें वकील करने, अपने परिजनों से बात करने, गर्म कपड़े, किताब व घर का खाना खाने की अनुमति दी थी।

इससे पहले दिशा को शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह पुलिस हिरासत में है। दिशा ने हिरासत में उक्त सामान देने की मांग करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने इसके अलावा टूलकिट मामले में एफआइआर, रिमांड एप्लिकेशन और अरेस्ट मेमो दिशा को उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी।

21 वर्षीय दिशा को किसानों के विरोध से संबंधित सोशल मीडिया पर कथित रूप से टूलकिट को संपादित करने और साझा करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने दिशा को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध छेड़ने के लिए टूलकिट के खालिस्तान समर्थ रचनाकारों के खिलाफ एक एफआइआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार दिशा रवि टूलकिट गूगल डॉक की संपादक है और दस्तावेज के निर्माण और प्रसार में महत्वपूर्ण साजिशकर्ता है। पुलिस ने कहा कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया और टूलकिट दस्तावेज बनाने के लिए दूसरों के साथ सहयोग किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने ट्विटर पर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए खालिस्तानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ सहयोग किया। दिशा ने ही ग्रेटा थनबर्ग के साथ टूलकिट डॉक साझा किया था।

सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर बनाई टॉप 10 में जगह, यूपी में अफसर बनेंगी विकल्प

नई दिल्ली। सरकारी स्कूलों को लोग कम आंकते हैं। मानते हैं कि उनमें पढ़ने वाले बच्चे अधिकारी नहीं बन सकते। सरकारी स्कूल से शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने वाली दिल्ली की बेटी विकल्प ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की पीसीएस-2019 में दसवीं रैंक हासिल कर लोगों का यह भ्रम तोड़ दिया है। विकल्प मानती हैं कि सरकारी स्कूलों का कोई %विकल्प% नहीं है। उनमें अच्छी शिक्षा दी जाती है, तभी इनके बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करना चाहती हैं।

विकल्प परिवार के साथ पुराना मौजपुर माता वाली गली में रहती हैं। इन दिनों बुलंदशहर के सिकंदराबाद कस्बे में मामा के घर पर हैं। उन्होंने फोन पर बताया कि दूसरे प्रयास में उन्हें इस परीक्षा में कामयाबी हासिल हुई है। वह पीसीएस-2020 के परिणाम का इंतजार कर रही हैं। उनको उसमें इससे भी बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है।

विकल्प ने बताया कि उत्तर प्रदेश लघु भारत की तरह है। देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। यहां हर वर्ग के लोग रहते हैं। यहां काम करना रोचक होगा। विकल्प ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय से इंटरमीडिएट किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कालेज से वनस्पति विज्ञान में स्नातक की है। इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। उनकी मां विमला दिल्ली के सरकारी स्कूल की सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। उनके पिता राम निवास बीमा क्षेत्र की निजी कंपनी से सेवानिवृत्त हैं। उनकी बड़ी बहन पीएचडी कर रही हैं। विकल्प ने बताया कि वह दो बार संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा भी दे चुकी हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने पीसीएस-2019 का अंतिम परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। इसमें मथुरा के प्रकाश नगर निवासी विशाल सारस्वत ने टॉप किया है, जबकि नैनी प्रयागराज के युगांतर त्रिपाठी दूसरे व इंदिरानगर लखनऊ की पूनम गौतम तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, दिल्ली की नीलिमा यादव ने 8वीं और विकल्प ने 10वीं रैंक हासिल की है। परीक्षा कुल 25 प्रकार के 453 पदों की कराई गई थी। 434 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल हुए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में वाहन चोरी का अर्धशतक लगाने वाला गिरफ्तार, 11 बाइक बरामद

नई दिल्ली। वाहन चोरी का अर्धशतक लगाने वाले शातिर चोर को पूर्वी जिला पुलिस ने उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान घड़ोली निवासी अश्वनी कुमार उर्फ गुलशन, इसके साथी पुष्पेंद्र व बबलू कुमार के रूप में हुई है। अश्वनी वाहन चुराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का सदस्य है, जबकि उसके दोनों साथी चोरी के वाहन खरीदते थे। अश्वनी दिल्ली-एनसीआर में 50 मोटरसाइकिलें चोरी कर चुका है। पुलिस ने उसके पास से 11 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।

जिला पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अंतरराज्यीय गिरोह का एक शातिर चोर मयूर विहार फेस तीन में आने वाला है। इंसपेक्टर दिनेश आर्या के नेतृत्व में एसआइ राजबीर, एएसआइ अनिल यादव व अन्य की टीम बनाई गई। टीम ने सलवान स्कूल के पास अपना जाल बिछाया। जैसे ही तीनों आरोपित दो मोटरसाइकिलों से वहां पहुंचे पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस जांच में दोनों मोटरसाइकिलें चोरी की निकलीं। पुलिस पूछताछ में अश्वनी ने बताया कि वह अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़ा हुआ है।

गणोश सुमित उर्फ लुक्का और मोंटी के साथ मिलकर मोटरसाइकिलें चोरी करता था। चोरी करने के बाद उन्हें अलग-अलग स्थान पर खड़ी कर देता था। बाद में उन वाहनों को बबलू व पुष्पेंद्र को बेच देता था। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर 11 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आरोपित पुष्पेंद्र ओला का कैब चलाता था। लाकडाउन में उसकी नौकरी चली गई थी।

आर्थिक तंगी की वजह से पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। इसी दौरान वह अश्वनी के संपर्क में आया और चोरी के वाहनों को खरीदकर बेचने लगा। वहीं, डॉ. हेडगेवार अस्पताल में मंगलवार को स्कूटी पार्किंग को लेकर वकीलों और डॉक्टरों के बीच हुई झड़प में फर्श बाजार थाना पुलिस ने वकील की शिकायत पर डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। एफआइआर में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. केके शर्मा व एएसआइ निहाल सिंह का नाम भी है। वहीं डॉक्टरों ने भी पुलिस को एक लिखित शिकायत दी है, जिसपर अभी मुकदमा नहीं हुआ है। इससे डॉक्टरों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी है।बुधवार को अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने वकील प्रदीप शर्मा की शिकायत पर केस दर्ज किया है।

बाजार में आएगी कोरोना की वैक्सीन, एम्स निदेशक डॉ. गुलेरिया ने बताया

नई दिल्ली। इस साल के अंत में खुले बाजार में कोरोना का टीका आ सकता है। एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया के अनुसार, फिलहाल निर्धारित लक्ष्य में शामिल लोगों का टीकाकरण हो रहा है। इसके बाद उपलब्धता के अनुरूप बिक्री के लिए बाजार में टीका उपलब्ध हो सकेगा। बुधवार को डॉ. गुलेरिया ने कोरोना टीके की दूसरी डोज ली और कहा कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। दोनों डोज में किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं आया। वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने सरकार की सूची में शामिल लोगों से आगे आकर टीकाकरण कराने की अपील की।

मीडिया से बातचीत में डॉ. गुलेरिया ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है। जल्द ही 50 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। टीकाकरण की शुरुआत काफी धीमी थी, लेकिन अब इसने गति पकड़ ली है। अब लोग टीका लगावाने के लिए आगे आ रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ गई है। इसलिए सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी केंद्र बनाए गए हैं। अपने देश की आबादी को देखते हुए काफी संख्या में लोगों को टीका लगना जरूरी है। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। पूर्व में हमलोग पोलियो सहित कई टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चला चुके हैं। इसी तरह कोरोना टीकाकरण में भी सफलता हासिल करेंगे। कोरोना पर जीत के लिए अधिक से अधिक लोगों में एंटीबॉडी विकसित करना जरूरी है।

डॉ. गुलेरिया ने कहा कि कई देशों में वायरस के नए स्ट्रेन सामने आए हैं। इसकी आशंका भारत में भी रहेगी, लेकिन अगर अधिक संख्या में लोग टीकाकरण करा चुके होंगे तो नए स्ट्रेन पर भी लगाम लग जाएगी।

डीएसएसएसबी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जातिगत प्रश्न पूछने पर दर्ज होगी एफआईआर, कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में दो बार जातिगत प्रश्न पूछने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। निर्देश दिया है कि इस अधिनियम में सक्षम अधिकारी द्वारा मामले की जांच की जाए।

उसकी मासिक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। अक्टूबर 2018 और अगस्त 2019 में डीएसएसएसबी ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति से जुड़े आपत्तिजनक प्रश्न पूछे थे।

इस मामले में अधिवक्ता डॉ. सत्यप्रकाश गौतम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी दायर कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया था कि अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान करने के लिए जानबूझ कर यह प्रश्न पूछे गए थे।

इस मामले में डीएसएसबी की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि उच्चाधिकारियों की समिति से जांच कराने के बाद ये प्रश्न पत्र बनाने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यही नहीं डीएसएसबी ने बंद लिफाफे में कोर्ट को उन लोगों की सूची सौंपी थी, जिन्होंने ये प्रश्न पत्र बनाए थे।

अक्टूबर में सुनवाई के दौरान डीएसएसएसबी के चेयरमैन संतोष वैद्य इस मामले में खेद भी जताया था। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र बेदी की कोर्ट ने इस मामले में आरोपितों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में दो बार जातिगत प्रश्न पूछने के मामले में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन को अदालत में पेश होना पड़ा था। उन्होंने कोर्ट के समक्ष खेद भी जताया था और कहा था कि पेपर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद संबंधित पुलिस थाने में आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाएगा।

दिल्ली-अंबाला ट्रैक पर चलने वाली आधा दर्जन ट्रेनों का आवागमन प्रभावित

नई दिल्ली (एजेंसी)।

किसान संगठनों के दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने भी एहतियात बरतते हुए आधा दर्जन मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दिया है। सोनीपत में किसानों के रेलवे ट्रैक पर बैठने से रोहतक-गोहाना-पानीपत रेल मार्ग पर गांव मुंडलाना स्टेशन पर इंजन रोका गया है। रोहतक में भी एक मालगाड़ी को रोका गया है, जिसे पानीपत जाना है। गोहाना स्टेशन पर एक मशीन रोकी गई है, जिससे गोहाना से पानीपत के बीच में रेलवे लाइन की मरम्मत की जानी है। 3 बजे- रेल चक्का जाम के चलते शाम 4 बजे तक दिल्ली-अंबाला ट्रैक पर चलने वाली बठिंडा एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस व रेलवे कर्मचारी स्पेशल ट्रेन का आवागमन प्रभावित होगा।

इस दौरान इंजन पर फूलमाला चढ़ाने के साथ चालक को फूल दिया जाएगा और यात्रियों को जलपान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन रोको कार्यक्रम का उद्देश्य बंद ट्रेनों को शुरू करवाना है। यूपी गेट स्थित धरनास्थल से कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। वहीं, रेलवे स्टेशनों, पटरियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे सुरक्षा विशेष बल के लगभग 20 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है।

2 बजे- गुरुग्राम के पातली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की खबर है।

2:15 बजे- ग्रेटर नोएडा के दनकौर में दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल को रोका गया। किसानों ने ट्रेन में लोगों फल वितरित कए।

12:35 बजे- दिल्ली के तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। प्रदर्शन की कोई सुगबुगाहट नहीं है। सीआरपी के जवान भी तैनात हैं।

12:40 बजे- दिल्ली से सटे गुरुग्राम के पातली रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने के लिए प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, जबकि पुलिस बल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों का दिल्ली-एनसीआर के चारों बॉर्डर (शाहजहांपुर, सिंघु, टीकरी और गाजीपुर) पर प्रदर्शन जारी है। इस बीच बृहस्पतिवार को होने वाले रेल रोको आंदोलन को लेकर किसान संगठनों के बीच असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। वहीं, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने गुरुवार दोपहर बारह बजे से चार बजे तक रेल रोकने का एलान किया है। हालांकि किसान संगठनों में इसको लेकर मतभेद सामने आए हैं और सांकेतिक रूप से ट्रेन रोकने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद पुलिस-प्रशासन व रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। सिंघु, टीकरी और अन्य उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि स्थानीय लोग ही अपने-अपने क्षेत्रों में ट्रेन रोकेंगे।

यूपी के प्रशांत कुमार बने जेएनयू के अध्यक्ष

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रशांत कुमार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन आफ इंडिया (एनएसयूआइ) का अध्यक्ष बनाया गया है। मूलरूप से उत्तर प्रदेश, कानपुर के घाटमपुर के रहने वाले प्रशांत कुमार जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं। प्रशांत ने 2019 में जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। एनएसयूआइ को जीत तो नहीं मिली लेकिन प्रशांत के नाम एक अनोखा रिकार्ड जरूर दर्ज हो गया। प्रशांत को एनएसयूआइ के अब तक के किसी भी प्रत्याशी के मुकाबले सर्वाधिक मत मिले थे। उन्हे चुनाव में 771 वोट मिले थे। इसके पहले 2017 एवं 2018 में जेएनयू छात्रसंघ चुनावों में एनएसयूआइ अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को 82 एवं 405 वोट ही मिले थे। 2019 में एनएसयूआइ जेएनयू इकाई के अध्यक्ष विकास यादव थे।

दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेल रोको आंदोलन के चलते ये 4 स्टेशन हैं बंद

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में किसान संगठनों का रेल रोको आंदोलन जारी है। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ रेल रोका आंदोलन शाम 4 बजे तक होगा। इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस की सलाह पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने टीकरी बॉर्डर समेत 4 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एहतियातन इन चारों मेट्रो स्टेशन के गेट शाम 4 बजे तक बंद किए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली मेट्रो के कई और स्टेशन भी बंद कराए जा सकते हैं। बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि - टिकरी बॉर्डर, पंडित श्री राम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशनों पर प्रवेश / निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली-एनसीआर में भी रेल रोको आंदोलन के चलते रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ मेट्रो स्टेशनों के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बृहस्पतिवार को ज्यादातर मेट्रो स्टेशनों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा की गई है। गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कृषि कानूनों को रद किए जाने की मांग को लेकर पिछले सप्ताह ही 18 तारीख को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान की घोषणा की थी। वहीं, इस घोषणा के मद्देनजर दिल्ली समेत देशभर में रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कि अरुण कुमार के मुताबिक, हमने कई राज्यों में रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) की 20 कंपनियों को तैनात किया है। इसका मकसद रेल संपत्तियों को नुकसान से बचाना है। हमारी कोशिश है कि यात्रियों को कोई असुविधा भी नहीं हो रेल रोको आंदोलन भी शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाए। यहां पर बता दें कि दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 85वें दिन में प्रवेश कर गया।

बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि – टिकरी बॉर्डर, पंडित श्री राम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशनों पर प्रवेश / निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं।

खोए स्वाभिमान को पाने का अभियान था मंदिर आंदोलन : भारत भूषण

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रांत कार्यवाह भारत भूषण ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को वापस लेने का आंदोलन महज मंदिर के लिए नहीं था, बल्कि वह सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता से डगमगाए देश के स्वाभिमान की वापसी का अभियान था। इजराइल के साथ विश्व में यह अकेली मिसाल है जहां के नागरिकों ने सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद अपने धार्मिक स्थल को पाया है। वह कांस्टीट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय राजधानी के व्यापारिक संगठनों की ओर से आयोजित श्रीराम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भूषण ने कहा कि हिंदू कभी पराजय स्वीकार नहीं करता, इसलिए कमजोर होने की गलतफहमी निकाल दें। हालांकि, सैकड़ों सालों की गुलामी से कुछ हीन भावना आ गई थी, जिसे इसे आंदोलन ने दूर कर दिया है। हमने जो प्रगति-तरक्की की है, वह पूरे विश्व को अचंभित करने वाली है। उन्होंने बताया कि कुल 108 एकड़ की जमीन में भव्य मंदिर के साथ अन्य सुविधाओं के इंतजाम की तैयारी है। इसके लिए आस-पास की जमीन क्रय करने की कोशिश के साथ निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। भूषण ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें गुलामी के प्रतीक चिह्नें को मिटाना चाहिए। तुगलक व औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का नाम अब हटना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित लोकल शॉपिंग कांप्लेक्स (एलएससी) फेडरेशन के संरक्षक सतीश गर्ग ने कहा कि यह सुखद क्षण है कि प्रभु राम ने हम लोगों को मंदिर निर्माण में हाथ बंटाने का काम सौंपा है। हमारा सब कुछ उन्हीं का दिया है। इस मौके पर दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री पूनम गुप्ता, एलएससी फेडरेशन के अध्यक्ष राजेश गोयल, दिल्ली किराना कमेटी के अध्यक्ष विजय गुप्ता, दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा व महामंत्री उमेश सेठ, दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट आर्गनाइजेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर व राजौरी गार्डन मार्केट के अध्यक्ष रमेश खन्ना समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे।

नर्सरी दाखिल शुरू पर अभिभावकों का केवल एक ही सवाल आखिर कब खुलेंगे स्कूल

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार से नर्सरी दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। पहले दिन प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही। काफी संख्या में अभिभावक आवेदन देने के लिए आगे आए, जबकि कुछ अभी पशोपेश में हैं, कि कौन से स्कूल में फॉर्म भरा जाए और कौन से में नहीं। विकासपुरी एच-ब्लाक स्थित ममता माडर्न सीनियर सेंकडरी स्कूल की प्रधानाचार्य पल्लवी शर्मा ने बताया कि पहले दिन करीब 400 फार्म ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रणाली में भरे गए है। फॉर्म भरने स्कूल आए अभिभावकों के मन में कई तरह के सवाल थे, जैसे कुछ का कहना था कि लॉकडाउन के चलते उनका बच्चा प्ले स्कूल नहीं जा सका, जिसके कारण उसकी बुनियादी पढ़ाई अधूरी रह गई है। अब क्या वह उस क्षति की पूर्ति कर सकता है?इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि स्कूल कब खुलेंगे? अभिभावकों की सवालों के जवाब देने व उनकी काउंसलिंग करने के लिए काउंटर पर कुछ अध्यापकों की विशेष ड्यूटी लगाई गई थी। पल्लवी शर्मा ने बताया कि नर्सरी कक्षा में 100 सीट है और आसपास रहने वाले व ऐसे बच्चे जिनके भाई-बहन पहले से स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरने आए अभिभावकों के लिए गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अभिभावकों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। अच्छी बात ये है कि अभिभावकों ने धीरज व शारीरिक दूरी का पालन करते हुए फॉर्म को भरा। कुछ अभिभावकों ने स्कूल देखने की भी इच्छा जाहिर की और कोरोना महामारी को लेकर स्कूल की व्यवस्था व तैयारी को सराहा। वहीं द्वारका सेक्टर-5 स्थित बीजीएस इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य पूनम गुप्ता ने बताया कि नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन की सुविधा केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है। अभिभावकों को स्कूल आने की जरूरत न पड़े, इसके लिए स्कूल की वेबसाइट पर सभी जानकारी को अपलोड कर दिया गया है।

दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करते समय न करें गलती, होगा आर्थिक नुकसान

नई दिल्ली। तकनीकी के युग में डिजिटल लेन-देन का तरीका लोगों का समय और पैसा दोनों बचा रहा है, लेकिन एक जरा सी गलती उपभोक्ता का भारी नुकसान भी करा सकती है। ऐसे में कोई खरीदारी कर रहे हैं या फिर कोई अन्य सेवा ले रहे हों तो उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे बेहद सावधानी के साथ डिजिटल पेमेंट करें। यह सतर्कता दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करने पर भी लागू होती है। चाहे आप घर पर लैपटॉप के जरिये मेट्रो का स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कर रहे हों या फिर मोबाइल फोन पर, दोनों ही स्थिति में सावधानी बरतें। बता दें कि 7 सितंबर के बाद दिल्ली मेट्रो का संचालन दोबारा शुरू होने के बाद लाखों यात्रियों ने डिजिटल भुगतान को अपना लिया है। दिल्ली मेट्रो यूं भी टोकन सिस्टम बंद कर चुका है, ऐसे में लोग सहज ही डिजिटल तरीके से स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कर रहे हैं। ज्यादातर लोग घर

पर ही स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करते हैं। उपभोक्ता ऑनलाइन रिचार्ज करने के दौरान भूलवश किसी अन्य के एकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड के साथ भी हो जाता है। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी जरूरी है। दिल्ली मेट्रो से जुड़े अधिकारियों की मानें तो किसी दूसरे के एकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने की सूरत में यह वापस मिलना बेहद मुश्किल होता है। पैसे की वापसी इस बात पर निर्भर करती है तो सामने कितना भला है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम अपने लाखों यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड से सफर करने की सुविधा के तौर पर ऑटो टॉपअप फीचर वाले स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर चुका है। इस ऑटो टॉप-अप फीचर वाले स्मार्ट कार्ड विशेषता यह है कि मेट्रो का स्मार्ट कार्ड रखने वाले उपभोक्ता भी इस फीचर को एक्टिवेट करा सकते हैं। मेट्रो यात्री इस ऑटो टॉप-अप फीचर से अपने स्मार्ट कार्ड मेट्रो स्टेशन के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) प्रवेश गेट पर ऑटोमेटिक तरीके से रिचार्ज करा सकते हैं। नया स्मार्ट कार्ड ग्राहकों के लिए ऑटो-पे एप के जरिये उपलब्ध होगा। ऐसे में ऑनलाइन रिचार्ज करते समय सतर्कता बरतना जरूरी है। डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक, कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन अनुज दयाल के मुताबिक, ऑटो पे के द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड में ऑटो टॉपअप की सुविधा है। इसमें जब कभी कार्ड की वैल्यू 100 रुपये से कम रह जाएगी तो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन प्रवेश गेट पर कार्ड में 200 रुपये अपने आप क्रेडिट हो जाएगा।

संपादकीय

सड़क पर गड़ी कीलों का संदेश

कुछ चाक्षुष अनुभव ऐसे होते हैं, जिन्हें आप हमेशा भूल जाना चाहेंगे। किसान आंदोलन के दौरान हाल में उन्हें और उनके ट्रैक्टरों को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा सड़कों पर गाड़ी गई लंबी नुकीली कीलें या कंसरटीना तारों के बाड़े ऐसे ही दृश्य हैं, जिन्हें देखते हुए वितृष्णा और दहशत एक साथ पैदा होती हैं। यह क्यों संभव हो रहा है कि लोकतंत्र बनने की प्रक्रिया में लगे एक समाज और अपने को उसके अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही पुलिस की जुगलबंदी ऐसे दृश्य निर्मित कर रही है, जो किसी भी सुसंस्कृत आंखों को रुचिकर नहीं लगेंगे।

इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि भारत में पुलिस की प्रतिक्रियाएं अक्सर गैर-पेशेवर कारणों से प्रभावित होती हैं। 26 जनवरी को जिस तरह से दिल्ली में घुसे अराजक ट्रैक्टर सुरक्षा चक्र तोड़ते हुए लाल किले तक पहुंच गए और बिना किसी बड़ी बाधा के उस पर एक धार्मिक झंडा फहरा दिया गया, उससे किसी को भी दिल्ली पुलिस को एक पेशेवर पुलिस बल मानने में दिक्कत होगी। अपनी शुरुआती नालायकी पर लीपापोती करने के प्रयास में दिल्ली पुलिस ने आंदोलन के अगले चरण को रोकने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर ऐसे इंतजामात किए कि कई सांसदों को सदन में कहना पड़ा कि ऐसे दृश्य तो उन्होंने पाकिस्तान की सीमा पर भी नहीं देखे हैं। पुलिस की हड़बड़ी में की गई अतिरेकी व्यवस्थाओं के कारण तलाशना बहुत मुश्किल नहीं होगा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व एक स्थिति के बाद पुलिस के नेतृत्व पर छोड़ दिया जाना चाहिए। किसी परिस्थिति में लक्ष्य निर्धारित होने के बाद उसे हासिल करने की रणनीति बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी इसी नेतृत्व की होनी चाहिए, पर ऐसा बिरले ही होता है। अमूमन पुलिस द्वारा तय की गई रणनीति में महत्वपूर्ण सुझाव गैर-पेशेवर सूत्रों से आते हैं और अक्सर वही अंतिम भी होते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में फैली अराजकता इसी का उदाहरण है। जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, उससे विश्वास करना मुश्किल होगा कि किसान मार्च से निपटने की रणनीति पुलिस का शीर्ष नेतृत्व बना रहा था या उसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर रहा था। पूरा देश दम साधे दिल्ली की सड़कों पर अराजकता और उससे निपटने में पुलिस की असफलता देख रहा था। यह सही है कि गणतंत्र दिवस के आयोजनों की विराटता और उन पर संभावित आतंकी खतरों के चलते दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता वही थी, पर इसके बाद भी जितने संसाधन उसके पास दिख रहे थे, वे दृढ़ता से और सही रणनीति से इस्तेमाल किए जाते, तो अराजकता काफी हद तक सीमित की जा सकती थी। छोटे परदे से चिपका देश दोनों पक्षों, किसानों और पुलिस के घात-प्रतिघात देख रहा था और किसी से यह छिपा नहीं रहा कि पुलिस कभी भी स्पष्ट नहीं थी कि उसे करना क्या है। कोई अदृश्य हाथ था, जो उसकी रणनीति में अपनी जरूरत के मुताबिक वक्ती बदलाव कर रहा था। नतीजतन, लाल किले में जो कुछ हुआ, उसके लिए कोई तैयार नहीं था। 26 जनवरी की असफलता के दौरान इस संयम के लिए तो दिल्ली पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए कि अपने कर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसने उपद्रवियों पर गोली नहीं चलाई और किसी इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ, पर इस सवाल का जवाब कहीं से नहीं मिलता कि आंसू गैस के गोलों व लाठीचार्ज के बाद उनके पास रबर बुलेट जैसे कम घातक विकल्प क्यों नहीं थे, जिनके चलते बिना जान लिए भी भीड़ को विसर्जित किया जा सकता था? पुलिस के पास स्टन ग्रिनेड या मिर्चों के छिड़काव जैसे विकल्प ज्यादा होने चाहिए, जो जान लेने की जगह भय उत्पन्न करें। इसके बाद 6 फरवरी के चक्का जाम के दौरान जिस तरह की नाकाबंदी दिल्ली सीमा पर की गई, वह किसी पेशेवर कार्रवाई से अधिक अपनी पिछली असफलता की खीझ निकालने का प्रयास अधिक लगता है। एक खराब आप्टिक की तरह बड़ी-बड़ी नुकीली कीलें सड़क पर गाड़ी गईं, रास्तों पर कंक्रीट के टुकड़े रखे गए या कंसरटीना तार बिछाए गए। हम यह भूल गए कि अब एक विश्व ग्राम में तब्दील दुनिया में जनांदोलनों से निपटने के लिए की जाने वाली राज्य की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय खुर्दबीन से होकर गुजरती है। मानवधिकारों का एक आम स्वीकृत स्तर है, जिसकी कसौटी पर कसने पर इन तस्वीरों से भारत की छवि धूमिल होगी और जिस तरह की अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं इन पर मिलीं, वे किसी भी तरह से उत्साह बढ़ाने वाली नहीं थीं। थोड़े धैर्य और कल्पनाशीलता से काम लिया जाता, तो इन्हीं उपायों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता था। मसलन, कीलों जड़ें लकड़ी के फट्टे सुरक्षित रखे जा सकते थे और जिन्हें जरूरत पड़ने पर किसी भी रास्ते पर तेजी से लगाया जा सकता था। इसी तरह कंसरटीना तार भी प्रशिक्षित टुकड़ी द्वारा समय रहते बिछाया जा सकता है। किसान कोई शत्रु देश के सैनिक नहीं हैं, जो रात के अंधेरे में अचानक हमला करेंगे। हर आंदोलन पूर्व घोषित होता है और पुलिस के अवरोध तोड़ने के पहले घंटों खींचातानी चलती है। हर बार इतना समय तो होता ही है कि पुलिसकर्मी जरूरत पड़ने पर उपरोक्त अवरोधक लगा सकें। यह सब नहीं किया गया और दिल्ली सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसा दिखने दिया गया, तो शायद इसके पीछे वह उतावली झुंझलाहट थी, जिसके लिए किसी पेशेवर पुलिस बल में जगह नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन का क्या नतीजा निकलेगा, इसका दारोमदार तो राजनीतिक नेतृत्व पर है, पर आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, इसकी कुछ हद तक जिम्मेदारी पुलिस बलों की भी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को अलग-अलग और एक साथ भी बैठकर इस पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जरूरत पड़ने पर उन्होंने आवश्यक मात्रा में बल प्रयोग नहीं किया और बिना जरूरत उन उपकरणों का प्रदर्शन किया, जिनसे मानवाधिकारों का सम्मान करने वाले लोकतंत्र का हमारा दावा निश्चित रूप से कमजोर पड़ा है । राजनीतिक नेतृत्व को भी इस तरह की परिस्थितियों में पुलिस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराने के साथ-साथ उन्हें फैसलों में पर्याप्त स्वतंत्रता देनी ही होगी, तभी संभव हो सकेगा कि समय पर पर्याप्त बल का प्रयोग हो और बेजरूरत उनका फूहड़ प्रदर्शन न किया जाए।

प्रवीण कुमार सिंह

किसान आंदोलन से उपजे हालात को देखते हुए देश के दुश्मनों को मतभेदों का लाभ उठाने से रोकें

चीन की गतिविधियों ने फिर से दर्शा दिया है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में राष्ट्रीय सहमति के आधार पर चीन को लेकर नए सिरे से दृष्टिकोण और नीति बनानी होगी। यह दृष्टिकोण साथ-साथ विकास की गुंजाइश जैसे किसी मुगालते के बजाय वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों के कारण बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां और तेजी से बदलते वैश्विक ढांचे और कोविड-19 जैसी महामारी के कारण बदलते समीकरण जैसे मसले हमारे राजनीतिक वर्ग की प्राथमिकता में होने चाहिए। इसका यही अर्थ है कि हमें किसान आंदोलन का तत्काल समाधान निकालना होगा।

किसी भी देश के नेताओं के लिए यह स्वाभाविक है कि वे राजनीति में सक्रिय रहकर अपने दल, कार्यक्रम और विचारधारा को प्रोत्साहन दें। इतिहास ने हमें यह सबक सिखाया है कि जब भी राजनीतिक वर्ग ने अपने संकीर्ण हितों की पूंति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की अनदेखी की तो देश को उसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। कई बार तो यह कीमत सदियों तक चुकाई गई। हमारी कमजोरियों का लाभ उठाकर देश के दुश्मन अगर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए तो भी वे उसे और कमजोर करने में सफल रहे। भारत में ऐसी स्थितियों के तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। भारतीय इतिहास का सबक स्पष्ट है कि चाहे कोई राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो या फिर विपक्ष में, उसे अपने राजनीतिक एजेंडे की पूंति करने के लिए किसी भी सूरत में देश के सुरक्षा हितों को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि फिलहाल देश सुरक्षा चुनौतियों के जोखिम से जूझ रहा है। इन चुनौतियों को देखते हुए राजनीतिक वर्ग के लिए यह आवश्यक है कि वह सुरक्षा चुनौतियों पर अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर किसी आम सहमति पर पहुंचे। व्यापक स्तर पर हो रहे वैचारिक टकराव के बावजूद सुरक्षा संबंधी इन मुद्दों का समाधान निकालना ही होगा, क्योंकि इन मुद्दों पर भारत के भविष्य को लेकर देश-विदेश में सवाल उठ रहे हैं।

राजनीतिक वर्ग को सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को इस प्रकार संभालना चाहिए कि वे सुरक्षा की चुनौती का सवाल न बन जाएं। किसानों के मौजूदा आंदोलन के संदर्भ में यह बहुत प्रासंगिक है। राजनीतिक वर्ग को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के दुश्मनों को

इसमें दखल देकर लाभ उठाने का कोई अवसर न मिले। इसे अनदेखा न किया जाए कि ब्रिटेन और कनाडा के साथ ही कई देशों में कुछ समूह खालिस्तान की मुहिम के लिए सक्रिय हो गए हैं। इन देशों में मुख्यधारा की राजनीति के कई नेता भी किसान आंदोलन पर अनुचित टिप्पणियां कर चुके हैं। भारत सरकार ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप वाली इन टिप्पणियों को खारिज करके उचित ही किया।

किसान आंदोलन से उपजे हालात को देखते हुए भारतीय राजनीतिक वर्ग को इन देशों से अधिक पाकिस्तान की भूमिका पर ध्यान देना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय सिख देशभक्त हैं और राष्ट्र के प्रति उनका अमूल्य योगदान है, जो निरंतर जारी है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान हमेशा से भारतीय सिख समुदाय को बरगलाने के प्रयास में जुटा रहा है। तमाम पाकिस्तानी विद्वान और सामरिक विशेषज्ञ मानते हैं कि विभाजन के दौरान सिखों को निशाना बनाना ऐतिहासिक गलती थी और यदि केवल हिंदुओं पर ही हमला किया जाता तो शायद सिखों ने पाकिस्तानी इलाकों से पलायन न किया होता। इस प्रकार हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों और सिखों की मजबूत दोस्ती गांठी जा सकती थी।

पाकिस्तानी विद्वान हिंदुओं और सिखों के बीच चले आ रहे रोटी और बेटी के रिश्तों के बावजूद ऐसी सोच रखते हैं। पाकिस्तानियों के ऐसे विचारों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां खालिस्तान सहित तमाम अन्य मुद्दों के माध्यम से सिखों को साधने की हरसंभव तिकड़में आजमा रही हैं। इस संदर्भ में मैं अपने राजनयिक दौर के कुछ अनुभव भी साझा करना चाहूंगा।

मैंने जब भी पाकिस्तानियों से पूछा कि जब दोनों देशों के बीच पंजाब सीमा पर कोई विवाद नहीं है तो फिर वे क्यों खालिस्तानी मुहिम का समर्थन करते हैं? इस पर उनका जवाब हमेशा गोलमोल रहता था। मैंने उन्हें बताया कि भारत इससे वाकिफ है कि तीर्थयात्रा के लिए पाकिस्तान जाने वाले सिख जत्थों के समक्ष वे खालिस्तान को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। आखिर जब तमाम सिखों को यह नागवार गुजरता है तब फिर वे अपनी आदत से बाज क्यों नहीं आते? इस सवाल का भी उनके पास कोई सीधा जवाब नहीं होता था। यह किसी से छिपा नहीं कि कई खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं।

जब पाकिस्तानी राजनयिकों का इस ओर ध्यान दिलाया जाता तो अधिकांश इससे इन्कार करते और या फिर चुप्पी साध लिया करते। इससे जाहिर होता है कि भारत की परेशानी बढ़ाने का पाकिस्तान कोई अवसर नहीं छोड़ेगा। किसी भी देश के राजनीतिक वर्ग को यह समझना चाहिए कि दुश्मनों को उसके सामाजिक एवं आर्थिक मतभेदों का लाभ उठाने का कोई मौका न मिले। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि सिखों की वफादारी असंदिग्ध है, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियां बहुत शातिर हैं। उन्हें किसी साजिश के लिए कोई अवसर न दिया जाए। सरकार और विपक्ष के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे किसान आंदोलन का मिलकर कोई ठोस समाधान निकालें।राजनीतिक वर्ग को दुनिया को यही संदेश देना चाहिए कि जब बात भारत के सुरक्षा हितों की आती है तो सभी राजनीतिक मतभेद किनारे कर दिए जाते हैं। वर्ष 1994 में ऐसा ही एक अवसर आया था, जब संसद ने दुनिया को संदेश देने के लिए सर्वानुमति से संकल्प पारित किया था कि जम्मू-कश्मीर में अपने हितों को लेकर भारत कभी कोई समझौता नहीं करेगा। फिलहाल वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन का रवैया भी लगातार आक्रामक बना हुआ है। उससे सैन्य एवं कूटनीतिक वार्ता जारी है, लेकिन यह सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है कि क्या वह गत वर्ष अप्रैल वाली स्थिति की ओर वापस लौटेगा? किसी भी सूरत में भारत 1998 की अपनी उस नीति पर कायम नहीं रह सकता, जो एलएसी पर शांति सुनिश्चित करने पर आधारित है।

चीन की गतिविधियों ने फिर से दर्शा दिया है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में राष्ट्रीय सहमति के आधार पर चीन को लेकर नए सिरे से दृष्टिकोण और नीति बनानी होगी। यह दृष्टिकोण साथ-साथ विकास की गुंजाइश जैसे किसी मुगालते के बजाय वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों के कारण बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां और तेजी से बदलते वैश्विक ढांचे और कोविड-19 जैसी महामारी के कारण बदलते समीकरण जैसे मसले हमारे राजनीतिक वर्ग की प्राथमिकता में होने चाहिए। इसका यही अर्थ है कि हमें किसान आंदोलन का तत्काल समाधान निकालना होगा।

नई श्रम संहिता पर अमल

संसद द्वारा पारित नई श्रम संहिता के मुताबिक बदलाव सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आजकल जोरों पर है। श्रम मंत्रालय इस कार्य में लगा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि 1 अप्रैल से, यानी अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से ये बदलाव लागू हो जाएंगे। ऐसे में कुछेक बड़े बदलावों के असर को लेकर कई तरह की शंका-आशंका भी कुछ हलकों में स्वभावतः दिख रही है। सबसे ज्यादा चिंता सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नए कानूनों में यह प्रावधान है कि कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट, ओवरटाइम और लीव ट्रैवल अलाउंस आदि अलग-अलग मदों में मिलने वाली राशियां सीटीसी (कॉस्ट टु कंपनी) के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकतीं। अगर ये ज्यादा हुईं तो अतिरिक्त राशि सैलरी में जुड़ी मानी जाएगी।

कहा जा रहा है कि इसका एक सीधा प्रभाव यह हो सकता है कि कर्मचारियों को हर महीने हाथ में आने वाली रकम में कमी का सामना करना पड़े। वजह यह कि तमाम तरह के भत्तों की सीमा सीटीसी का 50 फीसदी बंध जाने के बाद सैलरी का टैक्सेबल हिस्सा बढ़ जाएगा। मगर इसी का दूसरा पहलू यह है कि सैलरी मद में इजाफा होने पर कर्मचारियों की पीएफ राशि बढ़ जाएगी। इन्हीं कानूनों में ओवरटाइम की नई सीमा भी तय की गई है। नए प्रावधानों के मुताबिक निर्धारित समय से 15 मिनट भी ज्यादा काम किया तो संबंधित कर्मचारी का ओवरटाइम बन जाएगा। बहरहाल, हानि-लाभ के इस तात्कालिक गणित से अलग हटकर देखें तो सैलरी स्ट्रक्चर का नियमितीकरण एक बड़ी जरूरत है जो इस कवायद से पूरी हो रही है।

अभी देश में विभिन्न कंपनियों के सैलरी स्ट्रक्चर में कोई तालमेल ही नहीं होता। किस कर्मचारी का वेतन कितना तय हुआ है, उसे किन भत्तों के नाम पर कितना पैसा दिया जाता है और कब किस आधार पर उनमें कटौती हो जाती है, यह कंपनी विशेष की नीतियों पर निर्भर करता है। प्रफेशनल ढंग से काम कर रही कुछ कंपनियों में फिर भी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, पर ज्यादातर कंपनियों में उनकी वेतन संबंधी नीतियों का हमेशा कोई ठोस तार्किक आधार नहीं होता। वे तात्कालिक परिस्थितियों और कभी-कभी व्यक्ति विशेष की सोच, समझ या सनक पर आधारित होती हैं। कर्मचारियों के हितों के लिए ही नहीं, देश में कंपनियों और उनके कर्मचारियों के संबंधों में स्थिरता और कुछ हद तक एकरूपता लाने के लिहाज से भी यह एक जरूरी कदम है।

सभी संबंधित पक्षों की ओर से थोड़ी सावधानी और थोड़ा अतिरिक्त प्रयास इस महत्वपूर्ण बदलाव पर अमल को आसान बना सकता है। पहले चरण में इससे जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करते हुए अनुमानों और अफवाहों को खत्म कर दिया जाए तो सैलरी स्ट्रक्चर के तार्किकीकरण से संभावित नुकसानों को कम करने या उनकी भरपाई के तरीके निकालने का काम अगले चरण में हो सकता है।

पेड़ ही हैं हमारी असल पूंजी, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ प्रभावी लड़ाई में भी मिलेगी मदद

भारतीय मनीषा में असली समृद्धि के मायने को आधुनिक युग में एक बार फिर मुहर लगी है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रकृति को ही सबसे बड़ी पूंजी माना गया है, लेकिन उपभोक्तावाद की दुनिया ने इस सिद्धांत को तज दिया। तज क्या दिया, एक तरीके से बिसार दिया। हम आभासी समृद्धि के पीछे दौड़ने लगे और वास्तविक समृद्धि को उजाड़ते गए। आज जब देश की शीर्ष न्यायिक संस्था ने विशेषज्ञों की समिति के निष्कर्ष के आधार पर यह तय कर दिया कि एक वयस्क पेड़ हर साल करीब 75 हजार रुपये की कीमत का लाभ पहुंचाता है तो पता नहीं अपने किए पर उन लोगों को अफसोस हो रहा होगा कि नहीं, जिन्होंने जंगलों को उजाड़ आभासी विकास का रास्ता अपनाया है। बात बहुत सीधी थी, लेकिन सबके समझ में नहीं आई। हमारे ऋषि-मुनियों ने अपने आचार, विचार और व्यवहार से हमको सिखाया, समझाया। लेकिन भौतिकता के फेर में हम 'न माया मिली न राम' के शिकार हो गए। ऋषियों-मुनियों के आश्रम तो अब दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन अगर आप उनके चित्र देखें तो हरियाली और पेड़-पौधों से आच्छादित होते थे। ये उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हर जरूरत की पूर्ति करते थे। यही उनकी पूंजी होती थी। इस मान्यता को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्थापित किया है।

दरअसल पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई। यह याचिका बंगाल सरकार के उस कदम के खिलाफ थी जिसमें 500 करोड़ रुपये की लागत से पांच रेलवे ओवरब्रिज बनाने के नाम पर 356 पेड़ों की बलि तय हो चुकी थी। शीर्ष अदालत ने इन पेड़ों की कीमत तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति ने बताया कि एक पेड़ हर साल 74,500 रुपये का लाभ पहुंचाता है। पेड़ों द्वारा वायुमंडल में अवमुक्त की जा रही ऑक्सीजन की कीमत 45 हजार रुपये है।

अब आप कल्पना कीजिए कि असली धनवान कौन है। जंगलों को सहेजने-संवारने वाले हमारे आदिवासियों से धनी कौन है आज। भारी-भरकम बैलेंस शीट वाले देश के उद्योगपतियों के खाते में जमा धन से कितने ऐसे पेड़ खरीदे जा सकते हैं। सरकार का संबंधित मंत्रलय पेड़ों की कीमत का आकलन नेट प्रजेंट वैल्यू के आधार पर करता है जो बहुत ही संकीर्ण है। इस गणना के अनुसार एक हेक्टेयर या 2.4 एकड़ क्षेत्र में खड़े पेड़ों की कीमत का आकलन बहुत घने जंगलों के लिए अधिकतम 56 लाख रुपये और खुले जंगल (विरल पेड़) के लिए इतने क्षेत्र में मौजूद पेड़ों की कीमत 27 लाख रुपये आंकी जाती है। कोई भी यह सहज आकलन कर सकता है कि एक घने जंगल के 2.4 एकड़ में कितने पेड़ हो सकते हैं और यदि एक पेड़ की सालाना लागत करीब 75 हजार रुपये हो तो उस क्षेत्र के कुल पेड़ों की उनके पूरे आयुकाल की लागत क्या होगी?

कोई भी सरकारी परियोजना ऐसी नहीं है जिसके सिरे चढ़ने में प्रकृति का विनाश नहीं होता हो। पेड़ों का काटा जाना तय होता है। कई मामलों में तो पूरी परियोजना की लागत पेड़ों की इस नई कीमत से बहुत कम हो जाएगी। एक जमाना था जब दुनिया का हर भूभाग वनों से आच्छादित था। बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती जरूरत के चलते हरियाली के रकबे का अनुपात कम होता गया। यह प्रवृत्ति दुनिया के लगभग सभी देशों में दिखी। भारत जैसे प्रकृति प्रेमी देश में भी जरूरत प्रेम पर हावी रही। हमने ठाना कि देश के भूभाग का एक तिहाई रकबा जंगल से आच्छादित करके रहेंगे, लेकिन आज भी हम इसे हासिल नहीं कर सके हैं।

वर्ष 2019 की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल भौगोलिक रकबे में जंगल का रकबा 21.67 फीसद है। यदि इसमें पेड़ों को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल रकबा 24.67 फीसद हो जाता है। देश की बड़ी आबादी की जरूरतों के पूरा करने के लिए विकास अपरिहार्य है, लेकिन यह पर्यावरण के विनाश की कीमत पर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। संतुलन जरूरी है। विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन आसान रास्ते हमें ज्यादा रास आते हैं। हम सड़कों की जगह समुद्री और रेल मार्गों को विकसित करने पर ज्यादा जोर दे सकते हैं। परियोजनाओं की राह में आ रहे वृक्षों को स्थानांतरित किया जा सकता है। इस काम में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पेड़ काटना अपरिहार्य हो जाए तो ज्यादा संख्या में नए पेड़ लगाकर उनकी भरपाई की जा सकती है। भरपाई के क्रम में पौधरोपण तो होता है, पर वे पेड़ नहीं बन पाते हैं।

और अंत में अगर आप भी लखपति, करोड़पति बनना चाहते हैं तो पेड़ लगाना शुरू कीजिए। और अगर पेड़ लगा चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति के तय फामरूले से उनकी कीमत की गणना करके खुश रहिए कि आप कितने अमीर हैं। चाहे-अनचाहे रूप में आप मानवता की कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं। हर साल बड़ी कीमत की शुद्ध ऑक्सीजन वायुमंडल में भेज रहे हैं। वातावरण में मौजूद नुकसानदायक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े खतरे ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ आप प्रभावी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह खुशी सच्ची होगी। यही असली पूंजी है।

तेजी से बढ़ती बुजुर्गों की संख्या के बारे में सोचना होगा कि उनका जीवन सुचारु रूप से कैसे चले?

इस संगठन को चलाने वाले नाथूभाई लाल पटेल कहते हैं कि हर साल बुजुर्गों की ओर से आने वाले प्रार्थनापत्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले तीन हजार के करीब प्रार्थनापत्र आते थे। अब यह संख्या बढ़कर पांच हजार तक जा पहुंची है। नाथूभाई पूरे देश में घूम-घूमकर बुजुर्गों के लिए जीवन साथी खोजने के लिए ऐसे सम्मेलन आयोजित करते हैं। वह इस काम को सबसे बड़ी सेवा मानते हैं। साफ है जब देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो उनका जीवन भी सुचारु रूप से चले, इसकी व्यवस्था करने के बारे में सोचा जाना चाहिए।

हाल में इंदौर में निराश्रित बुजुर्गों को शहर से जबरन बाहर निकालने की घटना ने लोगों को ध्यान फिर से बुजुर्गों की ओर खींचा। बुर्जुगों की इस कदर अनदेखी-उपेक्षा के बीच पिछले दिनों एक सुखद खबर भी आई। एक महिला के पति की मृत्यु हो गई थी। बच्चे अपने-अपने परिवारों में व्यस्त थे। महिला नितांत अकेली थी। क्या करे। कोई सुख-दुख बांटने वाला भी आसपास नहीं था। उसने संन्यास ले लिया और हरिद्वार चली आई।

वहां वह साधु-संतों के बीच रहने लगी। वहीं उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। दोनों एक-दूसरे से सुख-दुख कहने लगे। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। दूसरे साधु-संतों ने यह देखा तो दोनों का विवाह करा दिया। इसी तरह कुछ दिन पहले एक वृद्धाश्रम में रहने वाले दो बुजुर्गों ने भी विवाह किया। इन दिनों होने वाले बहुत से ऐसे ही विवाह अपने देश में बदले हुए वक्त को बता रहे हैं। इन दिनों एक टूथपेस्ट के विज्ञापन में एक उम्रदराज महिला अपने बाल-बच्चों और नाती-पोतों को खाने पर बुलाती है। वह बार-बार बाहर की ओर देखती है। मानो किसी के आने का इंतजार हो। थोड़ी देर बाद एक बड़ी उम्र का आदमी उसका कंधा थामता है और वह महिला अपनी अनामिका में पहनी अंगूठी दिखाती है। यानी वह रिलेशनशिप में है और उसने मंगनी की अंगूठी पहन ली है। यह देखकर बच्चे पहले चकित होते हैं, फिर खुशी मनाते हैं। विज्ञापन की आखिरी लाइन है-नई आजादी का

जश्न। दिलचस्प है कि एक ओर स्त्री विमर्श विवाह को एक गुलामी की तरह देखता है तो दूसरी तरफ बड़ी उम्र में दूसरा विवाह करने वाली महिला उसे दूसरी आजादी का जश्न कहती है। अगर ध्यान से देखें तो समाज में परिवर्तन तो आ रहा है, मगर वह बहुत धीमा है। वैसे भी अपने देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ती जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार पांच करोड़ दस लाख बुजुर्ग पुरुष और पांच करोड़ तीस लाख बुजुर्ग महिलाएं हैं। ऐसे बुजुर्ग भी बहुतायत में हैं, जो जीवन साथी की मृत्यु, उससे अलगाव या बच्चों के कहीं दूर चले जाने के कारण अकेले रह गए हैं। इनकी संख्या डेढ़ करोड़ के आसपास है। अकेलापन इनकी बड़ी समस्या है। इनकी बात सुनने, बात करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। बहुत से बुजुर्ग आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं हैं, मगर सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता, जब तक कि जीवन में किसी इंसान का सहारा न हो।

अपने देश में इन दिनों बुढ़ापा काटना बहुत मुश्किल काम हो गया है। एक समय कहा जाता था कि महिलाएं चूंकि घर में रहती हैं और घर के तमाम कामों को निपटाने में ही उनकी उम्र बीत जाती है, इसलिए अगर वे अकेली रह भी जाएं तो भी अपना जीवन काट लेती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए अकेलापन काटना एक भारी समस्या होती है। हालांकि सच्चाई यही है कि बदले वक्त में जब पुरुष और स्त्री विभिन्न कारणों से जीवन के चौथेपन में अकेले रह जाते हैं तो उनका समय काटे नहीं कटता। वे अकेले घर में रहें तो कब तक। आखिर कितनी देर किसी से फोन पर बातें करें, टीवी देखें, फेसबुक पर रहें। बीमार पड़ जाते हैं तो और मुश्किल हो जाती है। कोई देखभाल करने वाला और अस्पताल पहुंचाने वाला तो चाहिए। ऐसे में अकेलेपन और भविष्य में आने वाली विपत्तियों के डर से वे अवसाद के शिकार हो जाते हैं। बुजुर्गों के लिए काम करने वाली संस्था एजवेल फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि हमारे यहां इन दिनों बुजुर्ग बेहद अकेले हैं। इसलिए यदि बहुत से बुजुर्ग अपने चौथेपन में भी साथी की तलाश कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य क्या, क्योंकि जब तक जीवन है उसे ठीक से और खुशी से जीने की चाह हर एक में हो सकती है। याद करें कि कुछ साल पहले मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक और मॉडल जैरी हाल ने विवाह की घोषणा की थी।

गुजरात के अहमदाबाद का एक संगठन है-बिना मूल्य अमूल्य सेवा। यह अकेले रह गए बुजुर्गों को मिलवाने के लिए सम्मेलन आयोजित कराता है। उसमें आकर अकेले रह गए बुजुर्ग एक-दूसरे से परिचय प्राप्त करते हैं। फिर पसंद आने पर यदि एक-दूसरे से विवाह करना चाहते हैं तो उनका विवाह करा दिया जाता है। यदि वे विवाह न करके लिव इन में रहना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी की जाती है। अनेक बार इस सम्मेलन में बच्चे अपने माता-पिता को लेकर आते हैं। यहां आने वाले बहुत से बच्चे कहते हैं कि अपने माता-पिता का अकेलापन वे चाहकर भी दूर नहीं कर पाते। अपने-अपने काम-धंधों और गृहस्थी की जिम्मेदारियों में फंसकर वे माता-पिता की समस्याओं को नहीं समझ पाते। वैसे अगर चाहें भी तो साथी की कमी किसी तरह दूर नहीं कर सकते। इसलिए वे उनके लिए यहां साथी खोजने चले आते हैं।

इस संगठन को चलाने वाले नाथूभाई लाल पटेल कहते हैं कि हर साल बुजुर्गों की ओर से आने वाले प्रार्थनापत्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले तीन हजार के करीब प्रार्थनापत्र आते थे। अब यह संख्या बढ़कर पांच हजार तक जा पहुंची है। नाथूभाई पूरे देश में घूम-घूमकर बुजुर्गों के लिए जीवन साथी खोजने के लिए ऐसे सम्मेलन आयोजित करते हैं। वह इस काम को सबसे बड़ी सेवा मानते हैं। साफ है जब देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो उनका जीवन भी सुचारु रूप से चले, इसकी व्यवस्था करने के बारे में सोचा जाना चाहिए। बूढ़ों के हिस्से में आया अकेलापन भी दूर होना चाहिए। औरों की तरह उन्हें भी सुख से जीने का पूरा अधिकार है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा और सदन से वॉकआउट

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरु हो गया है। आज बजट सत्र का पहला दिन ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरान अभिभाषण बड़े हंगामे की भेंट चढ़ गया। समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी तथा कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल के सामने प्रदर्शन के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। विधान भवन में विधानसभा सदस्यों तथा विधान परिषद सदस्यों के सामने जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण शुरू किया, वैसे ही सपा, बसपा व कांग्रेस के सदस्य उनके आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सभी ने एक साथ वॉकआउट कर दिया। इन सबके बीच भी राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान हंगामे के बीच में कहा कि कोरोना काल में सरकार ने अच्छा काम किया। इसको लेकर देश भर में प्रदेश सरकार की प्रशंसा की गई है। यहां हर जिले में आईसीयू की स्थापना हुई। प्रदेश मे तो एक्सप्रेस-वे तेजी से बनाए जा रहे हैं। नोएडा के जेवर में एशिया से सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। प्रदेश में तय समय पर गेहूं व धान की सरकारी खरीद हुई है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर पुलिस में भर्तियां हुई। शिक्षकों की भर्ती भी रिकॉर्ड संख्या में हुई है।

विपक्ष के वॉकआउट तथा नारेबाजी के बीच में भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पूरा किया और विधान भवन से प्रस्थान कर गईं। विधान मंडल सत्र में अभिभाषण देने के बाद वापसी के समय उनको बाहर तक छोडने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित भी आए।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज शुरु हुआ था और जैसे ही राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों को संबोधित करना शुरू किया विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा से वॉकआउट भी कर दिया। समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के नेताओं ने सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले भी किसानों के मुद्दों के साथ पेट्रोल-डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा के गेट पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। आज सदन में बहुजन समाज पार्टी के सात बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और अपने बैठने के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। बसपा के नौ विधायकों ने अलग बैठने की मांग की है। बसपा के पास अब सिर्फ छह विधायक बचे हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने वाले नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। यहां पर महिलाओं के

खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। प्रदेश में तो में जंगलराज है। उन्नाव की घटना पर सरकार मौन क्यों है। प्रेस को बैन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तो अभिभाषण नहीं पढना चाहती थीं। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने उनको मनाया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हम लोग राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करते हैं। हम यहां पर सरकार का भाषण सुनने नहीं आए हैं। राज्यपाल तो सरकार का भाषण सुना रहीं हैं। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि उन्नाव की घटना पर सरकार मौन है। वहां पर दो युवतियों की मौत पर पुलिस लीपापोती कर रही। हम लोग राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करते हैं। इससे पहले विधान भवन प्रांगण में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के नेताओं ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया।

बोतलों में पेट्रोल व डीजल लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता: विधानमंडल सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक तथा विधान परिषद सदस्य ने विधान भवन प्रांगण में हंगामा किया। यह लोग चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। पेट्रोल तथा डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही कानून-व्यवस्था को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं।विधान भवन जैसे संवेदनशील स्थान पर समाजवादी पार्टी के नेता तमाम सुरक्षा इंतजाम को धता बता बोतलों में पेट्रोल तथा डीजल लेकर प्रवेश कर गए। इस दौरान इन लोगों ने पेट्रोल तथा डीजल से भरी बोतलों के साथ प्रदर्शन किया।

किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के विधायक ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर विधान भवन पहुंचे। विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन तथा आनंद भदौरिया की इस दौरान सड़क पर काफी देर तक पुलिस से झड़प भी होती रही। इस दौरान विधानसभा मार्ग पर यातायात को रोक दिया गया है। किसी भी प्रकार के वाहन को इस मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं है।

कांग्रेसियों ने भी किया प्रदर्शन: समाजवादी पार्टी के विधायक तथा विधान परिषद सदस्यों के बाद कांग्रेस के नेता भी विधान भवन प्रांगण में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। नेता विधानमंडल दल अराधना मिश्रा मोना के साथ विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने भी मंहगाई, कृषि कानून तथा उत्तर प्रदेश की खराब कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बढ़ती महंगाई, बढ़ते अपराध, कृषि क़ानून, पेट्रोल - डीज़ल के बढ़ते दाम व अन्य कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया।

कोरोना संकट काल में 2021-22 में विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के इंतजाम हैं। सदन के भीतर सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गयी है। राज्यपाल आनंदीबेन सुबह 11 बजे संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इस दौरान विपक्ष के हंगामा करने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में बुधवार दोपहर एक बजे संपन्न बैठक में नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा लगभग छह माह बाद हम कोविड-19 संक्रमण की चुनौतियों का सामना करते हुए फिर मिल रहे हैं। सदन की मर्यादा को बनाए रखते हुए यदि गंभीर चर्चा हो तो सदस्यों की गरिमा और लोकतंत्र के प्रति आमजन की आस्था भी बढ़ेगी। सदन में हम सबका आचरण समाज को प्रभावित करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार कार्यवाही सफलतापूर्वक संचालित करने और सदस्यों के उठाए मुद्दों पर चर्चा के लिए सदैव तत्पर है। पूरा प्रयास होगा कि सभी विषयों पर सकारात्मक कार्यवाही हो।

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सदन के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित ने कहा कि सदन 18 फरवरी से 10 मार्च तक घोषित कार्यक्रमानुसार संचालित होगा। 18 फरवरी को प्रात: 11 बजे राज्यपाल का विधान मंडल की संयुक्त बैठक में अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा आरंभ नहीं होगी। निधन के निर्देश तथा नियम-56 लिए जाएंगे। 22 फरवरी को प्रात: 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 2021-22 का आय-व्यय का प्रस्तुतीकरण करेंगे। इसके बाद अभिभाषण पर चर्चा आरंभ होगी। सदन की कार्यवाही पेपरलेस बनाने का संकल्प भी दोहराया गया। इस बैठक में रमापति शास्त्री, स्वामी प्रसाद मौर्या, गुलाब देवी, फतेह बहादुर सिंह व योगेंद्र उपाध्याय के साथ प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे व प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह भी उपस्थित थे।

सबसे बड़े राज्य में ई-बजट पेश होगा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सत्र में सबसे बड़े राज्य का पहला ई-बजट प्रस्तुत होगा। सत्ता पक्ष व विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस दौरान ऐसा वातावरण रहे जो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हो। विधानसभा अध्यक्ष दीक्षित ने कहा कि देश की सबसे बड़ी विधान सभा होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम संविधान के प्रति प्रतिबद्ध परंपरा व संस्कृति के साथ निष्ठावान होकर सदन की कार्यवाही मधुरतापूर्वक चलायें।

संक्षिप्त खबर

रघुवर दास की व्यवस्था ही ठीक थी, उसी को लागू कर दीजिए मुख्यमंत्री जी!

धनबाद । सरकारी निविदा की निर्धारित राशि से 40 फीसद तक नीचे जाकर ठेकेदार काम की बोली लगाते थे। इस पर रोक लगाने की मांग झामुमो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष सह झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष अमितेश सहाय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है।

सहाय बुधवार की देर शाम रांची में मुख्यमंत्री के आवास पर हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में चल रहे सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया और उनसे बातचीत की। अमितेश सहाय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया कि पूर्व की सरकार में सरकारी कार्य की निविदा के लिए जो राशि निर्धारित होती थी, ठेकेदार उस निर्धारित राशि से 30 से 40 फीसद तक नीचे जाकर टेंडर उठाते थे। इसका परिणाम कार्य की गुणवत्ता पर पड़ता था। साथ ही कार्य करने वाले मजदूरों को भी कम राशि मिलती थी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से पहले यह व्यवस्था थी कि संवेदक निर्धारित राशि से अधिकतम दस फीसद ही नीचे जा सकते थे। इस व्यवस्था को फिर से चालू किया जाए। सहाय ने यह भी बताया कि यह नियम लागू हो जाने से सरकार के जितने भी निर्माण कार्य हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। अमितेश सहाय ने कहा कि उनकी मांग पर जल्द ठोस कार्रवाई करने और पुराने नियम को फिर से लागू करने का भरोसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। इस मुद्दे के अलावा सहाय ने धनबाद की औद्योगिक इकाइयों पर भी राज्य सरकार को ध्यान देने का आग्रह किया। साथ ही धनबाद में चल रहे व्यवसायिक प्रकोष्ठ की गतिविधियों की भी जानकारी दी।

लुधियाना में रिश्तेदारों ने महिला के अकाउंट से उड़ाए 17.50 लाख

लुधियाना । रिश्तेदारी की आड़ में पांच लोगों ने महिला को भरोसे में लेकर उसके अकाउंट से 17.50 लाख रुपये उड़ा मकान के दस्तावेज कब्जे में ले लिए। हालात यह हो गए कि अब वह पिस्तौल के बल पर उस मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि शिकायत और सब सबूत देने के सवा साल बाद भी पुलिस ने मामले को जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल रखा है। हर तरफ से हार चुकी महिला अब तक पुलिस कमिश्नर को 5 बार शिकायत दे चुकी है।

शिकायत में धूरी लाइन के आजाद नगर की गली नंबर 2 निवासी रेखा रानी ने बताया कि उसकी शादी चंचल सागर के साथ हुई थी, मगर कुछ ही समय बाद दोनों के बीच तलाक हो गया। तब हर्जाने के तौर पर उसके पति ने उसे 15 लाख रुपये दिए थे। उसके करीबी पांचों रिश्तेदारों को जब पैसे मिलने का पता चला तो उन लोगों ने उसे विश्वास में लेकर वह रकम बैंक में जमा कराने के लिए रजामंद कर लिया। उनकी बातों में आकर रेखा ने न केवल वो सभी पैसे उनके हवाले कर दिए। बल्कि जहां-जहां उन लोगों ने कहा उसने दस्तखत करके दे दिए। आरोपितों ने कुछ खाली चेक भी साइन करा कर ले लिए। रेखा के पास उसकी मां द्वारा दिए गए 10 लाख कीमत के जेवर थे। जिसे बेच कर आरोपितों ने उसे हैबोवाल के संगम पैलेस चौक में एक मकान खरीद दिया। मगर उसके दस्तावेज अपने ही पास रख लिए।

कुछ समय बाद उसे पता चला कि आरोपितों ने बैंक में रखे उसके 15 लाख रुपये निकाल कर हड़प लिए हैं। पीड़िता का एक अन्य बैंक में अकाउंट था, जिसमें ढाई लाख रुपये थे। आरोपितों ने वह रकम भी निकलवा ली। पीड़िता ने जब उनसे पैसों की बात पूछी तो वो उसे जान से मारने की धमकियां देने लगे। उसके बाद आरोपितों की नजर उसके मकान में पड़ गई। वो जबरदस्ती उस मकान की रजिस्ट्री अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए दवाब बनाने लगे। पीड़िता ने जब ऐसा करने से मना कर दिया तो एक आरोपित ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसका चेक बैंक में लगा कर बाउंस कराया और उसके खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक जगह उसका रिश्ता होने जा रहा था। मगर चूंकि आरोपितों का उसके घर में बेरोक आना जाना था। उन लोगों ने उसका रिश्ता तुड़वाने के लिए उसकी कुछ अश्लील फोटो तैयार करके उसके होने वाले पति को भेज दीं। बाद में पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने मकान उनके नाम पर नहीं कराया तो वो उन फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। पीड़िता ने मांग की है कि आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करके उसे इंसाफ दिलाया जाए।

बुद्ध पार्क में सीएम का पुतला फूंकने पहुँचे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा

हल्द्वानी । भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में बुद्ध पार्क में सीएम का पुतला फूंकने पहुँचे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। अफसरों के निर्देश पर पहुँची पुलिस ने कांग्रेस नेता से पुतला छीन लिया। इस कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच जमकर बहस भी हुई। हालांकि, पुलिस कांग्रेस जिला महामंत्री से पुतला छीनने में कामयाब हो गई।

शाम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुँच रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद के बाद जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। कल भी सीएम हल्द्वानी के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं, सरकार पर विकास कार्यों को ठप करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को जिला महामंत्री हेमंत साहू के नेतृत्व में कांग्रेसी बुद्ध पार्क में पहुँच गए। आक्रोशित लोगों ने कहा कि रिंग रोड, आईएसबीटी, चिड़ियाघर जैसे बड़े प्रोजेक्ट बीजीपी के राज में ठप हो चुके हैं। युवा, किसान समेत हर मुद्दे पर सरकार विफल रही।

रेलवे अधिकारी का सामान बता ट्रेन की पेंट्रीकार में रखा था रुपयों से भरा बैग, कानपुर में होनी थी डिलीवरी

कानपुर । दिल्ली से जय नगर जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्पेशल ट्रेन की पेंट्री कार में मिले 1.40 करोड़ रुपयों की डिलीवरी कानपुर में ही होनी थी। बीती रात लावारिस मिले यह रुपये फिलहाल आरपीएफ के मालखाने में ही जमा हैं। कर्मचारी किसी रेल अधिकारी का सामान समझकर 19 घंटे तक बैग को इस विभाग से उस विभाग भेजते रहे। बाद में शक होने पर बैग खोला गया।

बैग की सूचना सोमवार रात करीब दो बजे सबसे पहले कामर्शियल कंट्रोल रूम पर आई। फोन करने वाले ने खुद को मंडल का बड़ा अधिकारी बताते हुए कहा कि ट्रेन के पेंट्री कार में एक बैग है, उसे उतरवा लेना। ट्रेन प्लेटफार्म नंबर पांच पर रात 2:51 बजे पहुंची तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विजय शंकर ने बैग उतार लिया। इसके बाद रात 3.15 बजे दूसरा फोन कंट्रोल रूम नंबर पर आया।

फोन करने वाले ने बैग की डिलीवरी कैंट में कैंटीन साइड में खड़े व्यक्ति को देने के निर्देश दिए। बैग किसे देना है, उसका नाम पता नहीं बताया। इस पर कंट्रोल रूम से बिना परिचय बैग देने से इन्कार कर दिया गया। फिर फोन सहायक आयुक्त के कंट्रोल रूम पर आया। फोन करने वाले ने बैग मंगवाने की बात कही तो वहां से भी कर्मचारियों ने बैग मंगवा लिया। इस बीच शक होने पर रेलवे, आरपीएफ और जीआरपी अधिकारियों की उपस्थिति में मंगलवार शाम सात बजे बैग खोला गया तो इतने रुपये देख सबके होश उड़ गए।

इंटरकाम पर फोन से भ्रमित हुए अफसर- रुपयों से भरे बैग की डिलीवरी के लिए शातिरों ने रेलवे के कोड का इस्तेमाल करके इंटरकाम फोन पर काल की। इससे अफसर

भ्रमित हुए। सामान्य तौर पर रेलवे के इंटरकाम का प्रयोग रेलवे अधिकारी या कर्मचारी ही कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति ऐसे कोड के बारे में नहीं जानता। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जिसने भी फोन किया है, वह रेलवे के कोड और उनके नंबरों से बखूबी परिचित है। रेलवे अधिकारी बताते हैं कि गूगल की मदद से कोड लगाकर इंटरकाम पर फोन किया जा सकता है, लेकिन यह किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्पेशल ट्रेन दिल्ली से सोमवार रात 9:15 बजे चली थी। ठीक 15 मिनट पहले दो युवक ट्रेन के पेंट्री कार में पहुंचे थे। वेंडर राम केवट को रेलवे अधिकारी का सामान होने की बात कहकर बैग रख दिया था। एक युवक ने कहा था कि सामान कानपुर सेंट्रल पर या फिर प्रयागराज पर उतार लिया जाएगा।

खंगाला जा रहा पीएफआइ कनेक्शन- जीआरपी के मुताबिक, एक बात तो साफ हो गई है कि पैसा कानपुर में डिलीवर होना था। इतनी बड़ी रकम हवाला से जुड़ी हो सकती है। इसके साथ ही पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) के कनेक्शन को भी देखा जा रहा है। जीआरपी इंस्पेक्टर राम मोहन राय ने बताया कि पेंट्रीकार के मैनेजर और काम करने वाले एक दर्जन कर्मचारियों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। उधर, दिल्ली से भी सीसीटीवी फुटेज मंगाए गए हैं।

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा एक वर्ष बाद 21 को आएंगी लखनऊ, संगठन की तैयारियों की लेंगी टोह

लखनऊ । किसानों आंदोलन खड़ा करने के मकसद से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। लगातार किसान पंचायतें कर रही हैं। इसके बाद वह पूर्वांचल के दौरे पर निकलेंगी। इससे पहले वह जमीनी स्तर तक संगठन की टोह विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रियंका ने प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। सहारनपुर, प्रयागराज और बिजनौर का दौरा कर चुकीं हैं और अब 19 फरवरी को मथुरा में उनकी किसान पंचायत प्रस्तावित है। इसके साथ ही उनके आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। लेना चाहती हैं। इसके लिए प्रदेश प्रभारी पूरे एक वर्ष के बाद 21 फरवरी से छह दिन के प्रवास पर लखनऊ आ सकती हैं। तैयारियों के लिए उनकी टीम यहां पहुंच चुकी है।

विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रियंका ने प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। सहारनपुर, प्रयागराज और बिजनौर का दौरा कर चुकीं हैं और अब 19 फरवरी को मथुरा में उनकी किसान पंचायत प्रस्तावित है। इसके साथ ही उनके आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश प्रभारी 21 फरवरी को लखनऊ आ सकती हैं। वह लगातार छह दिन यहां रुककर प्रदेश मुख्यालय में संगठन सृजन अभियान की समीक्षा करेंगी। इस दौरान न्याय पंचायत, ब्लॉक, शहर, जिला और प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इसके अलावा एक-एक बैठक फ्रंटल संगठन के साथ ही ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगी, जो सक्रिय रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई अहम जिम्मेदारी नहीं है।

इस तरह संगठन को पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति समझाने के बाद वह खुद पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकलेंगी। इसी बीच प्रियंका के अयोध्या दौरे की भी चर्चा है। अभी प्रदेश प्रभारी का अधिकृत कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां परखने के लिए प्रियंका के निजी सचिव संदीप इक्षसह के साथ राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर और सचिन नाईक बुधवार को प्रदेश मुख्यालय पहुंच भी गए। उल्लेखनीय है कि एक वर्ष पहले 17 जनवरी, 2020 को प्रियंका लखनऊ आई थीं और तीन दिन तक रहीं। उसके बाद उनके आने की चर्चा तो होती रही, लेकिन कोरोना की वजह से कार्यक्रम टलता रहा।

जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप के बयान पर सिर धुन रहे लालू, डैमेज कंट्रोल को ले बेटे को दिल्ली बुलाया

पटना । राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार है। वे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आइसीयू से बाहर आ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने आरजेडी और बिहार की राजनीतिक गतिविधियों की खोज-खबर लेनी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार आइसीयू से वार्ड में शिफ्ट होने के बाद लालू ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को दिल्ली तलब किया है। माना जा रहा है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप के बयान से लालू खफा हैं। पार्टी में डैमेज कंट्रोल में जुटे लालू तेज प्रताप को मना सकते हैं। वे बेटे को सख्त हिदायत भी दे सकते हैं। विदित हो कि हाल ही में तेज प्रताप यादव ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष की जमकर खबर ली थी। तेज प्रताप ने कहा था कि जगदानंद सिंह उनकी अवहेलना करते हैं तथा उनके कारण ही उनके पिता बीमार पड़े हैं।

तेज प्रताप के इस बयान को जगदानंद सिंह ने पार्टी का आंतरिक मामला बताया था, लेकिन इसपर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।

तेज प्रताप के तेवर से तेजस्वी भी खुश नहीं- द्व जगदानंद के खिलाफ तेज प्रताप के तेवर से तेजस्वी यादव भी खुश नहीं हैं। किंतु मामला बड़े भाई का है, इसलिए पिता लालू के हवाले है। जो करना है अब उन्हें ही करना है।

रघुवंश प्रसाद सिंह का भी कर चुके अपमान- तेज प्रताप पहले भी कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह असहज कर चुके हैं। पिछले वर्ष सितंबर में उन्होंने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना एक लोटा पानी से कर दी थी, जिसके बाद लालू ने हस्तक्षेप किया और समझाया था। तेज प्रताप के माफी मांग लेने के बाद बात आई-गई हो गई थी।

पूरा परिवार दिल्ली में, वहीं सुलझेगा मामला- आरजेडी प्रमुख की तबीयत में सुधार की खबर के बाद पार्टी के कई नेता दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। अभी लालू का पूरा परिवार दिल्ली में ही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती भी दिल्ली में ही हैं। तेजस्वी तो पिछले कई दिनों से दिल्ली में ही जमे हैं। ऐसे में तेज प्रताप के बयान से हुए विवाद का मामला अब लालू परिवार दिल्ली में ही सुलझाएगा, ऐसा लग रहा है।

बिगड़ती जा रही कानपुर में भर्ती किशोरी की हालत, गांव में सपाइयों का हंगामा

कानपुर । असोहा थानाक्षेत्र के गांव में बुआ-भतीजी की मौत व एक किशोरी के गंभीर घायल होने की घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। पूरी रात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर डटे रहे और गहन पड़ताल की। गुरुवार की सुबह बसपा और सपा के नेताओं ने पीड़ित पक्ष के घर के बाहर धरना दिया। पुलिस की पूछताछ के बाद छोड़े गए पीड़ित पिता को धरना स्थल से हटाने जाने पर सपाइयों ने हंगामा किया। किशोरियों के शव पोस्टमार्टम के बाद गांव लाने से पहले प्रशासन ने सतर्कता के साथ तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कानपुर अस्पताल में भर्ती किशोरी की हालत बिगड़ती जा रही है।

बुआ-भतीजी दो किशोरियों की मौत के बाद तीसरी किशोरी की हालत बिगड़ती जा रही है। कानपुर के अस्पताल में भर्ती किशोरी को सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों की पूरी टीम उपचार में लगी है। अस्पताल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है, मीडिया कर्मियों को भी बाहर ही रोक दिया गया है। अस्पताल के हर फ्लार पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।

गांव में सपाइयों का हंगामा- पुलिस की पूछताछ के बाद लौटे पीड़ित पिता को सपाइयों ने धरने पर बिठा लिया। इसपर पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो हालात तनावपूर्ण हो गया। सपाइयों ने नारेबाजी के साथ हंगामा शुरू कर दिया। धक्का-मुक्की के बीच किसी तरह पुलिस ने पीड़ित पिता को निकालकर पड़ोसी के घर पर लिटाया है।

गांव में पुलिस बल तैनात- पोस्टमार्टम के बाद किशोरी के शवों को गांव लाने से पहले पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। गांव में आठ थानों का फोर्स तैनात किया गया है। इसके साथ खुफिया भी अलर्ट हो गई है। पुलिस आला अधिकारी गांव में डेरा जमाए हैं। शवों के दफनाने के

लिए गड्ढा खोदने आए पुलिस के बुलडोजर को स्वजन और सपाइयों ने वापस कर दिया है।

तीन डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम- मृतका दोनों किशोरियों के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में तीन डॉक्टरों का पैनल गठित कर दिया गया है। पैनल में एक महिला डॉक्टर, शुक्लागंज के प्रभारी चिकित्साधिकारी और जिला अस्पताल के डॉक्टर को शामिल किया गया है। इस दौरान पोस्टमार्टम हाउस के मुख्य द्वार से लेकर बाहर तक भारी फोर्स तैनात है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सीओ बीघापुर कृपाशंकर और सदर कोतवाली प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्र बाहर मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के बाद शवों के ले जाने के लिए मुख्य गेट पर एंबुलेंस भी तैयार करा दी गई है।

मृतका के पिता को पुलिस ने छोड़ा सपा-बसपा नेताओं का धरना शुरू होने के बाद पुलिस ने एक मृतका के पिता को थाने से छोड़ दिया है। वह गांव वापस आ गए हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ घटनाक्रम पूछताछ कर रही। धरने पर बैठे सपाइयों ने मृतका के भाई को भी छोड़ने का दबाव बनाया है। एएसपी विनोद पांडेय, एडीएम राकेश सिंह, एसड़ीएम राजेश चौरसिया, सीओ रमेशचंद्र प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

सपा-बसपा के नेताओं ने शुरू किया धरना- असोहा थाना क्षेत्र के गांव में गुरुवार सुबह सपा व बसपा के नेता और कार्यकर्ता पहुंच गये। सपा जिला उपाध्यक्ष सुनील रावत, बसपा जिला सचिव जय नारायण गौतम के साथ कार्यकर्ताओं ने मृतक किशोरियों के स्वजन को छोड़ने की मांग की। पुलिस पिता व भाई से थाने में बिठाकर पूछताछ कर रही है। इसे लेकर सपाइयों ने स्वजन को तत्काल छोड़ने की मांग की और पीड़ित परिवार के घर के निकट धरने पर बैठ गए। बसपा जिला सचिव जय नारायण गौतम ने स्वजन व मीडिया की उपस्थिति में शवों का पोस्टमार्टम कराने और अंतिम संस्कार कराने की मांग किया।

स्वजन व ग्रामीणों से रात भर पूछताछ- उन्नाव के असोहा में हुई घटना को शासन ने गंभीरता से लिया है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी बुधवार की रात भर अलर्ट रहे। रात में घटनास्थल पर पहुंची आइजी लक्ष्मी सिंह और फिर एडीजी जोन एसएन साबत ने छानबीन और पूछताछ करने के बाद थाने का रुख किया। इसके बाद देर रात दोनों अधिकारी डीएम रवींद्र कुमार और एसपी आनंद कुलकर्णी के साथ गांव पहुंचे। स्वजन व ग्रामीणों से रातभर पूछताछ चली। एडीजी जोन और आइजी रेंज के लखनऊ चले जाने के बाद एसपी गुरुवार सुबह करीब छह बजे फिर से घटनास्थल पर पहुंच गए। वह टीम के साथ घटनास्थल का फिर से निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस टीम खेतों में गेंहूं की फसल खड़ी होने की वजह से फसल का भी ध्यान रख रही है कि खराब न हो सके और साक्ष्य मिल जाएं। घायल किशोरी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सूत्रों की मानें तो पुलिस अफसरों को घटना में कई अहम सुराग मिले हैं, हालांकि अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं।

मुंबई में तेजी से बढ़ा कोरोना ग्राफ, एक दिन में 721 नए केस दर्ज

मुंबई । मुंबई में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के अनुसार 7 जनवरी के बाद बुधवार को यहां कोरोना के सबसे अधिक 721 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद शहर में कुल संक्रमित मामलों की संख्या 3,15,751 तक पहुंच चुकी है। तीन संक्रमितों की मौत होने के बाद मौत का आंकड़ा 11,426 तक पहुंच चुका है। पिछले दो दिनों से दैनिक मामले 500-अंक से नीचे बने हुए थे।

मुंबई में सोमवार को 461 और मंगलवार को 493 नए मामले दर्ज किए थे। जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,97,522 बतायी गई थी। बुधवार को 421 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। मंगलवार को सक्रिय रोगियों की संख्या 5,649 से बढ़कर 5,943 तक पहुंच गई थी। शहर में कोविड-19 मामलों की औसत वृद्धि दर 0.16 प्रतिशत है। बुधवार को मुंबई में 18,685 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया था जिसके बाद टेस्ट की कुल संख्या 30,58,146 तक हो चुकी है।

बीएमसी से मिली जानकारी के अनुसार शहर के 27 केंद्रों पर 8,400 व्यक्ति - 1,767 स्वास्थ्यकर्मी और 6,633 अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन दी गई, जिसमें कुल व्यक्तियों की संख्या 1,33,349 थी।बुधवार को किए गए 18,685 कोविड-19 परीक्षणों के साथ, परीक्षणों की कुल संख्या बढ़कर 30,58,146 हो गई।

बीएमसी के एक अधिकारी के मुताबिक, शहर के 27 स्वास्थ्य केंद्रों पर 8,400 व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन दी गई जिनमें 1,767 स्वास्थ्यकर्मी और 6,633 फ्रंटलाइन वर्कर शामिल थे। शहर में अब तक कुल 1,33,349 व्यक्तियों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इन 8,400 लोगों में से393 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। इसके साथ, दूसरी खुराक देने वालों की कुल संख्या 676 हो गई है।

बंगाल के चुनावी घमासन में सियासी हिंसा तेज, मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला, सीआईडी करेगी मामले की जांच

कोलकाता । बंगाल के चुनावी घमासन में सियासी हिंसा तेज होने लगी है। कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता पर बम और गोलियों से हमला किया गया था। अब बुधवार की देर रात कोलकाता लौटते समय मुर्शिदाबाद के निमतिता स्टेशन के पास सूबे के श्रम राज्यमंत्री जाकिर हुसैन पर बमों से हमला किया गया। उन्हें कोलकाता लाकर एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। उनके पांव- हाथ और शरीर के अन्य हिस्से में जख्म है। इस घटना में मंत्री समेत 22 लोग जख्मी हैं। उनमें से कुछ को जंगीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का कहना है कि वह स्थिर और खतरे से बाहर है। अब सूत्रों के अनुसार सीआईडी ने इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों द्वारा बम से किए गए हमले में मंत्री जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल सीआईडी ने इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है। मुर्शिदाबाद के निमटीटा रेलवे स्टेशन पर जांच चल रही है, जहां राज्य मंत्री जाकिर हुसैन कल अज्ञात लोगों द्वारा बम फेंके जाने से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है।

जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के अस्पताल में राज्य मंत्री जाकिर हुसैन से मिलने पहुंचीं। कल अज्ञात लोगों ने मुर्शिदाबाद में जाकिर हुसैन पर बम फेंका था जिससे वो घायल हो गए थे जानकारी के अनुसार मंत्री की हालत के बारे में बताते हुए मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक अमिय कुमार बेरा ने बताया कि जाकिर हुसैन की हालत स्थिर है और अब वे खतरे से बाहर हैं। उनके एक हाथ और एक पैर में

चोटें आई है। मंत्री को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हमले की निंदा की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हमले की निंदा की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, ÷मैं पश्चिम बंगाल के निमिता रेलवे स्टेशन पर बम हमले की निंदा करता हूं। मेरी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है।÷ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जाकिर हुसैन पर हुए हमले को ÷निंदनीय÷ करार दिया और राज्य में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की। धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रशासन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कानून के अनुसार तेजी से काम करने का समय आ गया है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है।

जानकारी हो कि मंत्री ट्रेन पकड़ने स्टेशन जा रहे थे। गाड़ी को छोड़कर जब वह प्लेटफार्म नंबर दो की ओर ट्रेन पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे, उनके साथ उनके कई समर्थक व सहयोगी भी थे जो जाकिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उसी समय अचानक उन पर बम फेंका गया। इसके बाद वहां चीख-पुकार मच गया। हमला किसने और क्यों किया, इसकी पुलिस जांच कर रही है। घटनास्थल के आस-पास लगे क्लोज सर्किट टीवी कैमरों से बदमाशों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है।

लेकिन एक मंत्री पर हमला क्यों किया गया? हमले के पीछे कौन है? यह सवाल उठ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जाकिर हुसैन जिले के पशु तस्करों के खिलाफ उन्होंने राज्य सरकार से लिखित शिकायत की थी। इलाके के कुछ व्यापारियों के साथ उनका विवाद भी था। नतीजतन, हुसैन लंबे समय से टारगेट पर थे। इसके अलावा उनके करीबियों का कहना है कि पार्टी के जिले के कुछ नेताओं के साथ भी उनकी दूरी थी। कुछ दिन पहले ही जाकिर हुसैन ने रघुनाथगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन पर हमला हो सकता है। घायल जाकिर हुसैन को रात में जंगीपुर अस्पताल से कोलकाता रेफर कर दिया गया। जिले के तृणमूल अध्यक्ष अबू ताहेर ने कहा कि जल्द से जल्द हमलावर की गिरफ्तारी हो। उनकी एसपी से बात हुई है। मुर्शिदाबाद से सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा हुसैन पर हमला यह बताने को काफी है कि राज्य की कानून व्यवस्था कहां पहुंच चुकी है। वह ईमानदार छवि के नेता हैं और वह पशु तस्करों के खिलाफ आवाज उठाते थे। यही उनका अपराध है। राज्य में एक भी मंत्री सुरक्षित नहीं है।

एक नजर

ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी की दरगाह के लिए चादर शरीफ रवाना

जबलपुर। ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफअजमेर के लिए मंडी मदार टेकरी से चादर शरीफ रवाना हुई। बुधवार को मंडी मदार टेकरी स्थित बबलू होटल के सामने से अजमेर शरीफ चादर लेकर एक जत्था रवाना हुआ। चादर रवानगी की दौरान अकीदतमंदों ने इसकी ज्यारत की। इस अवसर पर हाफिज करीम साहब, चांद कुरेशी, बबलू कुरेशी, गोगा पहलवान, डॉ. महमूद अहमद वारसी, असलम इत्र वाले बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदुस्तान में अमन शांति के लिए दुआ खैर की।

भदभदा वाटरफॉल और सिलुआ घाट को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग

जबलपुर। मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के को-चेयरमैन आरके सिंह सैनी व प्रवक्ता राधेलाल गुप्ता ने शहर के भदभदा वाटरफॉल व सिलुआ घाट को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की मांग सरकार से की है। जिसमें कहा गया है संस्कारधानी जबलपुर में शहर से लगी हुई नर्मदा नदी एवं गौर नदी के संगम के एक ओर भदभदा वाटर फॉल व दूसरी ओर सिलुआ घाट है, जो कि अत्यंत चौड़ा एवं सूर्यास्त के समय चमकती हुई लहरें अत्यंत मनोहरी दिखती है। उक्त स्थल एक किमी. के दायरे में है। सदस्यद्वय ने इस संबंध में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, मप्र शासन के मुख्य सचिव, जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, पनागर विधायक सुशील इंदू तिवारी व ग्राम सिलुआ के ग्राम सरपंच को ज्ञापन भेजकर जनहित में शीघ्र ही पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की है।

जेलर दिलीप नायक के दो गीतों का विमोचन

सिहोरा। नगरपालिका परिषद के स्वच्छता अभियान के लिये सिहोरा जेलर दिलीप नायक द्वारा दो गीत बनाये हैं। जिसकी सीडी का विमोचन नंदनी मरावी विधायक सिहोरा द्वारा किया गया । सीडी में पहला गीत घर कचरा गाडी आई एवं दूसरा गीत बात मोरी ना बिसारिओ बुंदेली गारी की धुन पर जेलर नायक एवं उनकी बड़ी बहिन श्रीमती शशि नायक ने गाया एवं गीत की रचना जेलर नायक,बड़ी बहिन श्रीमती माला नायक ने की है। दोनों गानों का विमोचन बसन्त पंचमी के अवसर पर ज्वालामुखी देवी मंदिर में विधायक द्वारा किया गया । नगरपालिका प्रशासक एवं एसडीएम मो.शाहिद खान और सीएमओ श्रीमती जयश्री चौहान की पहल पर बनाये गये गीतों की प्रशंसा की गई । इस अवसर पर दिलीप दुबे, राजामोर ,शिशिर पांडे, अभिषेक परौहा, माधव मिश्रा, विनय जैन, विजय श्रीपाल,सुशील वर्मा,ब वन श्रीवास्तव, विजय बैगा, सुजीत पटैल, इंतियाज खान, शिवम तिवारी, राजेश ठाकुर आदि उपस्थित रहे।

सिहोरा में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आज

सिहोरा। आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के उदेश्य से भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के संयोजन में गुरुवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है । नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक परौहा ने बताया की होटल यशराज में सम्मेलन का आयोजन सांसद राकेश सिंह , विधायक सिहोरा तथा प्रदेश मंत्री श्रीमती नंदनी मरावी, विधायक बहोरीबंद प्रणय पांडे , एवं भारतीय जनता पार्टी जबलपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष सुभाष रानू तिवारी की उपस्थिति में दोफहर 11 बजे से किया जा रहा है जिसमे सभी सिहोरा नगर के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओ मातृशक्ति तथा युवा साथियों से पहुचने की अपील की गई है ।

नजूल भूमि के भूखंडों एवं निर्मित भवनों का किया निरीक्षण

जबलपुर। अपर कलेक्टर संदीप जीआर ने बुधवार को नजूल भूमि के पट्टा नवीनीकरण के लिए आयोजित विशेष शिविरों के निरीक्षण हेतु रसल चौक, नागरथ चौक, कांचघर एवं रांझी क्षेत्र का भ्रमण कर आवासीय एवं व्यावसायिक उपयोग किये जा रहे भू.खंडों एवं भवनों का निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान पाया गया कि आवासीय भूमि उपयोग के पट्टों पर नजूल ब्लाक नं 3, प्लाट नं 27/7 रकबा 3595 वर्गफुट धारक सुब्रत कुमार, सुजीत कुमार पिता बीपी पाल के द्वारा व्यावसायिक हीरो वर्कशॉप उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार प्लाट नं 27/4 रकबा 4800 वर्गफुट, मनोहर लाल पिता बाबूलाल ;व्यावसायिक दुकानेंद्ध प्लाट नं 13/5 रकबा 1500 वर्गफुट चंद्रवती पति एमएस शिवहरे ;हीरो एजेंसी के भू.खंडों का नवीनीकरण नहीं कराया जाना पाया गया। अपर कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान पाया कि पिछले 21 वर्ष 1999 से 2021 तक की अवधि व्यतीत होने के बाद भू.खंड धारकों द्वारा नवीनीकरण नहीं कराया गया है। मौके पर उपस्थित संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षकों को नजूल पट्टा नवीनीकरण के कार्य में प्रगति लाने एवं ऐसे समस्त भू.खंडों पर नियमानुसार पुनः प्रवेश की कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु निर्देशित किया गया।

1.45 करोड़ रुपए से होगा आदर्श पार्क का निर्माण

सिहोरा। जल प्लावन की समस्या से निराकरण के साथ-साथ नगर की बहुप्रतीक्षित आदर्श पार्क निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है संयुक्त संचालक नगरी प्रशासन विभाग द्वारा नगर पालिका सिहोरा को संचित निधि से बाह नाला के विकास एवं सौंदर्यीकरण तथा प्रस्तावित पार्क की बाउंड्री वाल के कार्य हेतु 1 करोड़ 45 लाख 77 हजार एवं जल प्लावन की समस्या से निपटने वार्ड क्रमांक 6, 7,8 में नाला निर्माण हेतु संचित निधि से आहरण की स्वीकृति 36 माह में पुनः जमा करने की शर्त के साथ प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि सिहोरा नगर पालिका क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों द्वारा लंबे समय से पार्क निर्माण के अलावा नगर के गंदे पानी की निकासी के साथ-साथ बरसाती पानी की निकासी हेतु वार्ड क्रमांक 6 ,7 एवं 8 में कनाड़ी बाह्य नाला तक नाला निर्माण की मांग की जा रही थी । इसकी स्वीकृति मिलने के उपरांत टेंडर जारी होने के बावजूद उक्त दोनों सौगात का लाभ राशि ना होने के कारण नगर वासियों को नहीं मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विधायक नंदनी मरावी ने सक्रियता के साथ विधानसभा में मामले को उठाते हुए लगातार प्रयास एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जन भावनाओं से अवगत कराते हुए नगर पालिका द्वारा पारित प्रस्ताव संचित निधि से उक्त निर्माण को कराए जाने की स्वीकृति खिलाते हुए पार्क निर्माण सहित नाला निर्माण की सौगात नगर वासियों को प्रदान की है।

बेरोजगार महासंघ ने कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारे

जयपुर। राजस्थान के बेरोजगारों ने चार विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा की है। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ ने लोगों से कहा कि चाहे हमें वोट दे या नहीं दें, लेकिन कांग्रेस अवश्य हराएं। महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस ने बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। इस कारण बेरोजगार युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। प्रदेश के सरकारी विभागों में चल रही भर्तियों को पूरा करने और नियुक्तियां देने की मांग को लेकर बेरोजगार पिछले तीन दिन से जयपुर में धरना दे रहे हैं। सरकार ने अब तक इनसे बात नहीं की तो इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

अब इन्होंने उप चुनाव वाली चार सीटों सुजानगढ़ में भागीरथ, सहाड़ा में प्रकाश चंद शर्मा,वल्लभनगर में सविता कंवर और राजसमंद में नंदलाल भील को उम्मीदवार घोषित किया है। अब तक चुनाव आयोग ने चारों सीटों पर होने वाले उप चुनाव की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन बेरोजगार महासंघ ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों ये उम्मीदवार मैदान में चुनाव होने तक टिक पाएंगे या फिर पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। पिछली भाजपा सरकार के समय महासंघ ने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन बाद में कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। यादव ने कहा कि अब वे कांग्रेस सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।

गौरतलब है कि राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पार्टी महासचिव अजय माकन द्वारा किया गया वादा एक बार फिर पूरा नहीं हो सका। प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं से किए गए वादे माकन दूसरी बार पूरा नहीं कर पाए हैं। माकन ने इस माह के शुरू में कहा था कि 15 फरवरी तक जिला स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों का काम पूरा कर लिया जाएगा। तय समयसीमा बीतने के बाद कांग्रेसियों में खलबली मचने लगी है। कांग्रेसियों के बीच इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बिना चर्चा किए ही वादा करते हैं? मुख्यमंत्री फिलहाल किसी भी तरह की राजनीतिक नियुक्ति करने के मूड में नहीं हैं।

राजसमंद में मंत्रियों का जमावड़ा, वैभव गहलोत को लेकर नहीं खोले राज

उदयपुर । राजसमंद विधानसभा उप चुनाव से पहले मंत्रियों का जमावड़ा वहां शुरू होने लगा है। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के अलावा चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना एवं कांग्रेस के अन्य कई प्रदेश स्तरीय नेता उदयपुर आकर राजसमंद रवाना हुए। इन नेताओं ने फिलहाल प्रत्याशी को लेकर राज नहीं खोला लेकिन कहा कि कांग्रेस प्रदेश की चारों विधानसभाओं में जीत दर्ज करेगी। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि उदयपुर संभाग में चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं, जबकि डूंगरपुर में पहले खोल दिया गया। अब केवल प्रतापगढ़ और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज नहीं है और यहां जल्द ही पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की योजना है। उन्होंने दावा किया कांग्रेस वल्लभनगर, राजसमंद, सहाड़ा के साथ सुजानगढ़ सीट बड़े अंतर से जीतेगी।

धारीवाल बोले, विकास संबंधी कार्य देखने आए- यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि वह उप चुनाव की तैयारी को लेकर नहीं, बल्कि राजसमंद में विकास कार्य की जानकारी लेने आए हैं। जिले की ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं जो लंबित हैं। उनकी जानकारी लेकर प्रायोरिटी से पूरा कराया जाएगा।

वैभव गहलोत का नाम मीडिया की उपज बताया- विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी एवं कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे तथा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत का नाम मीडिया की उपज है। राजसमंद से किसको को उम्मीदवार बनाना है, अभी पार्टी को तय करना है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रसोई गैस की बढ़ती कीमतों तथा पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार रसोई व पेट्रोल के दाम पर ध्यान नहीं दे रही। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दुनिया में कच्चा तेल सस्ता है, और भारत में पेट्रोल महंगा हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र के शासन से जनता परेशान और त्रस्त हो चुकी है। उनकी मोदी सरकार की कथनी व करनी में अंतर है। ऐसे में बढ़ती महंगाई की मार को कम करने के लिए जनता वोट से जवाब देगी।

कोरोना फाइटर पर जानलेवा हमले से फैला आक्रोश

ईएसओ इंडिया ने किया एसपी कार्यालय का घेराव

जबलपुर (एजेंसी)। कोरोना फाइटर घनश्याम चक्रवर्ती के उपर हुए जानलेवा से आक्रोश फैल गया है। बुधवार को अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन ईएसओ इंडिया द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई। घेराव से पूर्व ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

आधारताल सीएसपी अशोक तिवारी ने ईएसओ पदाधिकारियों से प्रदर्शन खत्म करने का आग्रह किया साथ ही दोषियों पर तत्काल कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। ईएसओ राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार चक्रवर्ती ने बताया की विगत कुछ दिनों पहले आधारताल निवासी घनश्याम चक्रवर्ती जो की ईएसओ का सक्रिय पदाधिकारी हैं एवं श्रमिक संघ के अध्यक्ष है साथ ही वरिष्ठ समाजसेवी भी है जिन्होने कोरोना काल के दौरान लगातार जनसेवा का कार्य किया। उसपर पड़ोस मे रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तलवार से जानलेवा हमला किया गया है। लेकिन राजनतिक नेताओं के दबाव के चलते आधारताल पुलिस द्वारा दोषियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नही की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान ईएसओ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण सिंह , सतीश कोरी, विपिन दत्ता, लोकेन्द्र सिंह, लोकेश कोष्ठा, अभिषेक गोलदार, सतीश विश्वकर्मा, अनुसिया रजक, आरती ठाकुर, दिलीप चौधरी, राम रतन, रामाराव मागरदे, दुर्गा कोल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मदनमहल अंडरब्रिज आरयूबी का कार्य 75 दिनों में पूरा

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। दरअसल मदनमहल अंडरब्रिज के पास आरयूबी विकास के लिये तीन महीनें का कार्य 75 दिनों में ही पूरा कर लिया गया है। जिससे अब जल्द ही अंडरब्रिज को लोगो के आवागमन के लिये खोल दिया जायेगा। पमरे मुख्य जन संपर्क अधिकारी प्रियंका दीक्षित ने बताया कि मदन महल स्टेशन के पास अंडर पास (आरयूबी) के विकास के लिए विगत 01 दिसंबर 2020 से तीन महीने के लिए मदन महल आरयूबी को सड़क यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। पमरे के निर्माण विभाग द्वारा आरयूबी विस्तार का कार्य 90 दिनों के लक्ष्य से पहले मात्र 75 दिनों में ही पूरा कर लिया गया है। जो कि पश्चिम मध्य के लिए लिये बहुत बड़ी उपलब्धि है । अतः आम जनता के उपयोग हेतु मदन महल आरयूबी को सड़क यातायात के लिए 22 फरवरी 2021 प्रातः 11 बजे से खोल दिया जाएगा ।

कोरोना संक्रमण को देख मुंबई सतर्क: लोकल में चढ़ी मेयर किशोरी पेडणेकर बोली- ठीक से पहने मास्क

मुंबई । मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर भी सड़क पर उतर आईं। किशोरी पेडणेकर ने हाथ जोड़कर लोगों से मास्क लगाने की अपील की। मेयर ने कहा अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो मजबूरी में लॉकडाउन लागू करना होगा। मेयर पेडणेकर ने मुंबई लोकल और दुकानों में भी गई और बिना मास्क के दिख रहे लोगों की जमकर फटकार लगाई। बता दें कि मुंबई में बीते सात दिनों में 24 हजार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है जिसके बाद महाराष्ट्र में सक्रिय मरीजों की संख्या 37 हजार हो गई है। मेयर ने स्टेशन पर एक खानपान स्टाल पर कुछ विक्रेताओं को ठीक से मास्क नहीं पहने हुए पाया। पेडणेकर ने उनसे हर समय मास्क पहनने का अनुरोध किया और दिशानिर्देश को नजरअंदाज करने पर उन्हें पुलिस कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अधिकारी ने कहा, बिना मास्क के 10 प्रतिशत यात्री शेष 90 प्रतिशत यात्रियों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।

होटल में छापा मारा- सीएसएमटी के बाद, पेडणेकर सांताक्रूज़ गईं, जहां उन्होंने एक होटल पर छापा मारा, जहां कई लोग जो खाड़ी देशों से लौटे थे, उन्हें कोविड -19 प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन में रखा गया था। यात्रियों की सूची में से चार यात्री होटल से गायब थे। मेयर ने लापता यात्रियों और होटल के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।

बीएमसी की चेतावनी - बीते कुछ दिनों में मुंबई के चेंबूर और तिलकनगर इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। बीएमसी ने कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए यहां के कई इलाकों को सील करने की चेतावनी दी है। चेंबूर में 550 हाउसिंग सोसाइटी को लोकल लॉकडाउन लगाने की चेतावनी वाला नोटिस भी भेजा जा चुका है।

नशे में धुत बेटे ने भुला दी मां की ममता: मां को उतारा मौत के घाट, पिता एवं बहन को मारने दौड़ा

भुवनेश्वर । शराब के नशे में धुत एक बेटे ने मां की ममता को भूल गया। जिसने जन्म दिया, पालन पोषण कर बड़ा किया, शराब के नशे में धुत बेटे उसी को भुजाली से बेटे ने मौत के घाट उतार दिया है। यह घटना ओडिशा प्रदेश के बालेश्वर जिला अन्तर्गत खइरा थाना क्षेत्र के मीरपुर खइरा गांव में घटी है।

खबर के मुताबिक बुधवार देर रात को रघुनाथ शिअल का छोटा बेटा जगबन्धु शियाल शराब पीकर नशे में धुत होकर घर लौटा। घर को लौटने के बाद मां मणि शिआल के साथ कहासुनी हुई। इसके बाद वो लाठी एवं भुजाली से पिता एवं बहन को मारने के लिए दौड़ा। पिता एवं बहन जान बचाकर भागे और गांव के अन्दर चले गए। घर पर जगबन्धु की मां बच गई थी। जगबन्धु ने फिर मां के ऊपर लाठी एवं भुजाली से हमला बोल दिया। नशे में धुत जगबन्धु ने अपनी मां की इस कदर पिटाई कर दी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ समय बाद परिवार के लोग घर पर लौटे और मणि शिआल को खून से लथपथ देख पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटे के इस कृत्य की स्थानीय लोगों ने कड़ी निंदा की है। लोगों का कहना है कि हर दिन वह शराब पीकर आता था और सिर्फ घर के लोगों को ही नहीं बाहर के लोगों के साथ गाली गलौज करता था। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

ब्राह्म समाज करेगा मेधावी बच्चों का सम्मान

सिहोरा। ब्राह्मण समाज सिहोरा की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन समाज के अध्यक्ष प्रकाश कुमार पांडे के निवास पर किया गया। इसमें आगामी बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार सदस्यता अभियान चल रहा है तथा उसके बाद निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न कराया जायेगा इसके साथ ही अगले माह होने वाले समाज के दसवी बारहवीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान समारोह के संबध मे भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर समाज के उपाध्यक्ष जयप्रकाश दुबे, अश्वनी कुमार पाठक,नंदकिशोर परौहा,प्रवीण गौतम,राकेश पाठक,शिशिर पांडे,रवि दुबे,राजेन्द्र दुबे,गोपाल पाठक,अनुरुध त्रिवेदी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे ।

समाज में श्रीराम के चरित्र और प्रतीक के रूप का निर्माण करें

जबलपुर। हमारा धर्म तोड़ने का कार्य नहीं करता बल्कि जोड़ता है, भारत में जितने भी पंथ और मंत हैं, वह तोड़ने की शिक्षा नहीं बल्कि जोड़ने के उपदेश देते हैं, ऐसी विशाल दृष्टिकोण और आत्मीयता के सहारे भारत को विश्व गुरु बनाने सभी को मिलकर कार्य करने होंगे भगवान श्रीराम ने भी सभी को जोड़ा, साथ ही सभी के सुखों की चिंता भी की, इस कारण हम आज भी हजारों वर्षों बाद भी श्रीराम को याद करते हैं और आज भी रामराज लाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के मन में श्रीराम का आदर्श व चरित्र गहराई तक बैठा हुआ है। भारत देश श्रीराम को पाकर प्रगति एवं दिशा पा रहा है अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हमें भवन के रूप में नहीं बल्कि समाज में श्रीराम के चरित्र व प्रतीक के रूप में स्थापित करना है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु संघ एवं विहिप के कार्यकर्ता प्रतिदिन की भांति आज रामपुर, विजयनगर छापर की श्रीराम महिला मंडली की महिला सदस्यों ने श्रीराम मन्दिर निर्माण मे निधि भक्तिभाव से समर्पित की, बस्ती के पालक छोटे लाल पटैल, बस्ती प्रमुख किशोर खत्री उपस्थित थे। श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण के लिए श्रीजानकी रमण कॉलेज रानीताल के प्रिंसिपल अभिजात कृष्ण त्रिपाठी द्वारा व श्रीजानकी रमण न्यास के अध्यक्ष शरद भाई की राशि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिये भेंट की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग प्रचारक राघवेंद्र, डॉ रामकिंकर मिश्रा, डॉ राणा, प्रध्यापक, मातृशक्ति एवं छात्र छात्राऐं उपस्थित रहे। जबलपुर माढोताल बस्ती में दुर्गा वाहिनी की बहनों ने राम श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु घर-घर पहुंचकर समर्पण निधि अर्पण कराई इस अवसर पर नेहा प्यासी पूजा रजक उपस्थित थे।

बाथरूम में संदिग्ध हालत में मृत मिले मूक-बधिर युगल, गीजर से गैस लीकेज के कारण मौत की आशंका

अहमदाबाद । गुजरात के सूरत में सगाई के बाद साथ रह रहे मूक बधिर युगल बाथरूम में संदिग्ध हालत में मृत पाया गया। पुलिस प्राथमिक दृष्टया मौत का कारण गीजर से निकली गैस से दम घुटने को मान रही है। सूरत के नानपुरा इलाके में रहने वाले अर्पित मनोज कुमार पटेल 24 की सगाई सूरत के ही कामरेज इलाके के राज नए सोसायटी में रहने वाली धृति ट्रेलर 21 एक के साथ हुई थी। दोनों की सगाई पिछले माह 31 जनवरी को हुई थी तथा 9 फरवरी से दिए दोनों मूकबधिर युवक-युवती साथ रहने लगे थे। बुधवार शाम जब अर्पित पटेल की बहन रितु पटेल नौकरी से लौट कर घर पहुंची तो अपने भाई अर्पित तथा उसकी मंगेतर धृति को फ्लैट में नहीं पाया। इधर-उधर देखने के बाद जब रितु ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो अवाक रह गई। अर्पित तथा धृति बाथरूम में अचेत पड़े थे जिन्हें चिकित्सकों को दिखाने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों के शव को पोस्टमार्टम के

कोरोना महामारी के दौर में बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए टिप्स

टीचर, ग्रुप स्टडी और दोस्तों के साथ पढ़ाई से आप एक तरह से वंचित हो चुके हैं, इसलिए समय प्रबंधन आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। अब टाइम टेबल के अनुसार विषय वाइज पढ़ाई कीजिए और इससे निश्चित रूप से परीक्षा हाल में आपको बेहतर परिणाम दिखेगा।

कोरोना महामारी ने जिन सेक्टर्स को सर्वाधिक डिस्टर्ब किया है, उनमें से एजुकेशन सेक्टर प्रमुख है। अगर यह कहा जाए कि पूरे साल को कोविड-19 ने, एजुकेशन के लिहाज से बर्बाद कर दिया, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से कुछ स्कूल और दूसरी शैक्षणिक संस्थाएं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश जरूर करती दिखीं, परंतु स्कूलों में होने वाली पढ़ाई और वहां मिलने वाला पढ़ाई का माहौल, अगर घर पर ही मिल जाए, तो फिर स्कूल की जरूरत ही क्यों पड़े? परंतु हकीकत यह है कि बावजूद तमाम मुसीबतों के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि सीबीएसई द्वारा घोषित हो चुकी है। 4 मई से 10 जून तक यह परीक्षाएं चलेंगी और इसका परिणाम जुलाई में घोषित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तैयारी कर ली है। कमोबेश इसी से मिलते जुलते डेट्स तमाम राज्यों के बोर्ड भी जल्द ही घोषित कर देंगे।

ऐसे में बच्चों के सर पर एग्जाम का बोझ तो आ ही गया, बेशक उनकी पढ़ाई हुई हो या नहीं! मतलब परीक्षाएं होंगी। हालांकि इसके लिए अभी समय जरूर है, पर अगर आज से ही सजगता नहीं बरती गई, तो इसके परिणाम बहुत बेहतर नहीं आएंगे और इस बात का यकीन जितनी जल्दी से जल्दी कर लिया जाए, तो बेहतर रहेगा!

टाइम टेबल

जी हां! कहते हैं कि संसार में एक समय ही ऐसी चीज है, जो कभी रुकता नहीं है! अगर आपने बीआर.चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत के एपिसोड देखे हैं, तो उसमें ''मैं समय हूं'' का मशहूर संवाद अवश्य ही सुना होगा। सच तो यह है कि अगर आप समय की कीमत नहीं समझते हैं, तो सामान्य दिनों में भी आप बहुत अच्छा परिणाम नहीं ला सकते हैं, और हाल फिलहाल तो कोरोना वायरस आपका आधा समय यूं ही निकाल चुका है। टीचर, ग्रुप स्टडी और दोस्तों के साथ पढ़ाई से आप एक तरह से वंचित हो चुके हैं, इसलिए समय प्रबंधन आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। अब टाइम टेबल के अनुसार विषय वाइज पढ़ाई कीजिए और इससे निश्चित रूप से परीक्षा हाल में आपको बेहतर परिणाम दिखेगा।

हेल्थ के बिना कुछ भी ठीक नहीं!

स्कूल जाने पर आप ना चाहते हुए भी काफी कुछ पढ़ लेते थे, शारीरिक भाग दौड़ भी हो ही जाती थी, किंतु लॉकडाउन में और उसके बाद स्कूल नहीं खुलने से आप कहीं आलसी तो नहीं हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाह हो गए हैं? खैर, अब सजग हो जाइए! सुबह जगने से लेकर, नाश्ता, पौष्टिक भोजन और शाम को थोड़ा बहुत टहलने से लेकर, सही समय पर सोना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और हां! सुबह सुबह व्यायाम करने से आपका पूरा दिन तरोताजा रहता है और इससे आप तो बेहतर स्टडी अवश्य कर सकते हैं। एक बार पुन: इस बात को दोहरा लीजिए कि बगैर उत्तम हेल्थ के आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा और किताब खोल कर बेशक आप बैठे रहें, परंतु आपको, आप ही के मन मस्तिष्क द्वारा बेहतर परिणाम नहीं प्राप्त होगा।

पूछिये, ढूँढिये, किंतु भटकिये नहीं!

लॉकडाउन में आप इंटरनेट की मदद लेना तो सीख ही गए होंगे, किंतु इंटरनेट पर कितना भटकाव है, यह भी आप महसूस अवश्य कर चुके होंगे। पहले आपने सोशल मीडिया इत्यादि पर समय नुकसान किया ही होगा, तमाम गैर जरूरी वीडियोज देखा होगा, दोस्तों के साथ गेम और चैट में समय खराब किया होगा, पर अब यह ना करिए! आप इंटरनेट की मदद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूर कीजिए, किंतु समय नुकसान ना हो, उस पर भटकिए नहीं! इंटरनेट जहां फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं यह आपका समय कितनी जल्दी व्यतीत कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बेहद सजगता के साथ ही इंटरनेट ब्राउजिंग करें और अपने घड़ी की सुईयां देखते रहें। साथ ही इंटरनेट के अलावा भी आप अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें तनिक भी हिचकिचाहट पालने की जरूरत नहीं है।

शांत वातावरण में रिवीजन

जिस प्रकार से जिम में एक बॉडीबिल्डर रोज एक ही व्यायाम का अभ्यास करता है, ठीक उसी प्रकार आपको अपने सब्जेक्ट का लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, उसका रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, जल्द ही कन्फ्यूजन में बदल जाएगा। वहीं इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। अगर आप किसी टॉपिक को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, तो रिवीजन करने से निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस प्राप्त हो जाएगा। हालांकि इसके लिए कोशिश करें कि आपको थोड़ा पीसफुल एनवायरमेंट मिले। टेलीविजन, इंटरनेट और दूसरे म्यूजिक इत्यादि माध्यमों से दूर रहकर एकांत में रिवीजन करने से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इस बात में दो राय नहीं है।

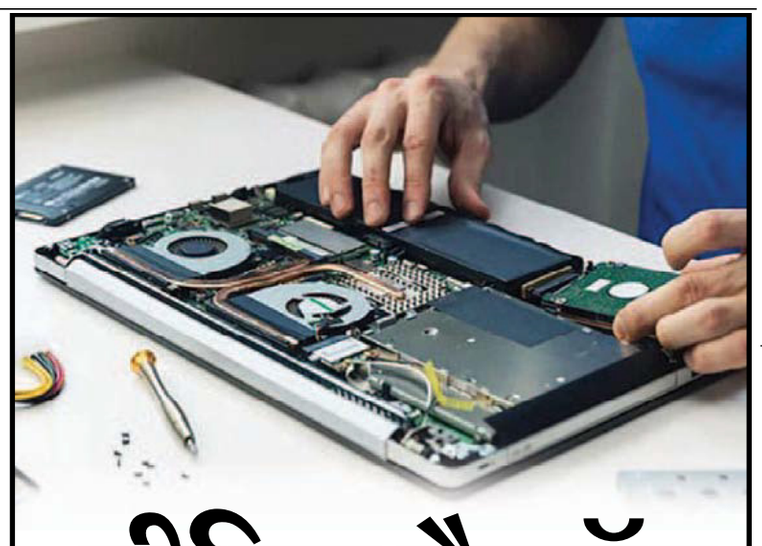

सीखिए लैपटॉप रिपेयरिंग और बनाएं उज्ज्वल भविष्य

लैपटॉप रिपेयरिंग के क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता का होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से दसवीं व बारहवीं के बाद लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं। आप इस क्षेत्र में शार्ट टर्म कोर्स से लेकर सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं।

इस बात में कोई शक नहीं नहीं है कि लैपटॉप आज के समय में हमारे दैनिक जीवन की एक आवश्यकता बन गया है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बैंकिंग व ऑफिस के काम आदि निपटाने के लिए हर व्यक्ति लैपटॉप को प्राथमिकता देता है। कुछ समय पहले तक जहां डेस्कटॉप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इनसे ज्यादा लैपटॉप को तवज्जो मिलने लगी है, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक है। ऐसे में लैपटॉप रिपेयरिंग के क्षेत्र में भी कॅरियर की नई संभावनाएं पैदा हुई है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं लैपटॉप रिपेयरिंग के क्षेत्र में कॅरियर-

स्किल्स- कॅरियर एक्सपर्ट के अनुसार, लैपटॉप रिपेयरिंग के क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों के भीतर सीखने की गहन इच्छा होनी चाहिए। इसके अलावा आपको लैपटॉप हार्डवेयर की भी अगर थोड़ी-बहुत जानकारी होगी तो यह आपके लिए अच्छा होगा। इस क्षेत्र में छात्रों में मार्केट में लॉन्च हो रहे नए लैपटॉप व उनकी क्वालिटीज के बारे पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के अपडेट होने के साथ-साथ अगर आप भी खुद को अपग्रेड रखते हैं तो इससे आपको अतिरिक्त लाभ होगा।

कोर्स- लैपटॉप रिपेयरिंग के क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता का होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से दसवीं व बारहवीं के बाद लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं। आप इस क्षेत्र में शार्ट टर्म कोर्स से लेकर सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इनकी अवधि तीन से छह माह तक हो सकती हैं।

संभावनाएं- कॅरियर एक्सपर्ट बताते हैं कि लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद आपके पास काम की कोई कमी नहीं होती। दरअसल, आज के समय में लैपटॉप हर व्यक्ति की जरूरत बन गया है और इसलिए उसकी रिपेयरिंग के लिए एक्सपर्ट की डिमांड भी बढ़ी है। कोर्स करने के बाद आप लैपटॉप व कंप्यूटर रिपेयर शॉप्स, लैपटॉप सेल्स सेंटर, लैपटॉप शोरूम, लैपटॉप सर्विस सेंटर आदि में काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ समय के अनुभव के बाद आप खुद की लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप भी खोल सकते हैं।

आमदनी- इस क्षेत्र में आमदनी मुख्यत: आपके अनुभव और स्किल्स के आधार पर तय होती है। कोर्स करने के बाद आप शुरूआती दौर में 15000 से 20000 रूपए महीना सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समय के अनुभव के बाद आपकी सैलरी में इजाफा होता है। इतना ही नहीं, अगर आप खुद की लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप खोलते हैं तो आपकी मासिक आमदनी हजारों से लेकर लाखों में हो सकती है।

पैनडेमिक सिचुएशन से उबारने के विशेषज्ञ बनें, बनेगा बढ़िया कॅरियर

जिस तरीके से कोविड-19 ने विश्व भर में विस्तार पाया है, कम से कम उस स्तर पर किसी बीमारी का तीव्र विस्तार ना हो सके। जाहिर तौर पर इस स्थिति को पहचानने और महामारी के भिन्न लक्षणों का स्तर, कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट ही समझ सकता है।

कोविड-19 ने जिस प्रकार से समूची दुनिया को हिला कर रख दिया है। इससे लोग एक बार फिर सोचने को मजबूर हो गए हैं कि क्या हमारे पास महामारी से संबंधित ढेर सारे विशेषज्ञ होने चाहिए, जो ऐसी स्थिति आने पर अपने ज्ञान और अपने जज्बे से हमें इस मुसीबत में फंसने से बचा लें। खुदा न खास्ता अगर मुसीबत में कोई फँस भी जाता है, तो जिस तरीके से कोविड-19 ने विश्व भर में विस्तार पाया है, कम से कम उस स्तर पर किसी बीमारी का तीव्र विस्तार ना हो सके। जाहिर तौर पर इस स्थिति को पहचानने और महामारी के भिन्न लक्षणों का स्तर, कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट ही समझ सकता है। ऐसे में आपके सामने एपिडेमियोलॉजिस्ट बनने हेतु कॅरियर में अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आइये जानते हैं.

वास्तव में देखें तो दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ''पहला सुख, निरोगी काया''। कल्पना कीजिए कि किस स्तर का डर फैल जाता है, अगर स्वास्थ्य पर संकट आ जाए। बात और भी गंभीर हो जाती है अगर कोई एक बीमारी समूचे विश्व पर एक महामारी की शक्ल में आये। ऐसे में कुछ भी कहना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि तब स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी किसी बीमारी की रोकथाम के फुलप्रूफ इंतजाम होने चाहिए। ऐसे में एपिडेमियोलॉजिस्ट का प्रोफाइल यहां बेहद कामयाब दिखता है। इसमें किसी बीमारी की पहचान और वह कितनी तेजी से फैल सकती है और उसे प्रभावी ढंग से कैसे रोक सकते हैं, यह कार्य अपने रिसर्च के द्वारा एक एपिडेमियोलॉजिस्ट ही कर सकता है।

एपिडेमियोलॉजिस्ट में मुख्यत: दो भाग हैं, जिसमें एक रिसर्च फील्ड से संबंधित है तो दूसरा क्लीनिकल फील्ड से संबंधित है।

वस्तुत: यह पूरी तरह से प्रोफेशनल होते हैं जो महामारी जैसे रोगों में लोगों की प्रतिक्रिया से लेकर, जेनेटिक बीमारी और बायो टेररिज्म तक पर कार्य करते हैं। इसके लिए आपके पास एक मास्टर डिग्री होना चाहिए। हमारे देश की बात करें तो इसके लिए 12वीं पास स्टूडेंट, जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ली हुई है। वह बीएससी अथवा दूसरे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अपना दाखिला करा सकता है और ऐसे ही जब आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो यह जान लें कि किसी भी यूनिवर्सिटी से कम से कम 55 फीसदी मार्क आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके पश्चात एपिडेमियोलॉजिस्ट के संबंध में प्रचलित तमाम कोर्सेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें बैचलर आफ साइंस, पब्लिक हेल्थ में बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। इसके बाद मास्टर ऑफ साइंस एपिडेमियोलॉजिस्ट में आता है। तत्पश्चात पीजी डिप्लोमा और अंत में आप एपिडेमियोलॉजिस्ट से पीएचडी कर सकते हैं। अथवा पब्लिक हेल्थ से पीएचडी कर सकते हैं।

स्कूल की बात करें तो दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू, मुंबई स्थित होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद है। ऐसे ही चेन्नई में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एपिडेमियोलॉजी स्थापित है। इसके अलावा आईआईटी के विभिन्न संस्थान इसकी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आईआईटी गांधीनगर, टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज मुंबई, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, पटना, जिसके नाम से भी जाना जाता है।

फ्रेशर्स के लिए बेहद काम के हैं यह कॅरियर टिप्स

अधिकतर कंपनियां ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहती हैं जो टीम में बेहद अच्छी तरह काम करना जानते हों। ऐसे में अगर आप फ्रेशर हैं और अपने कॅरियर को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको टीम में काम करना आना चाहिए।

पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब छात्र अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखते हैं तो उनकी जिन्दगी काफी बदल जाती है। कॉलेज की मौज-मस्ती के बाद उन्हें अपने कॅरियर को लेकर काफी सजग होना पड़ता है, ताकि वह अपना बेहतर भविष्य बना सके। कॅरियर में ग्रोथ के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप बार-बार अपनी जॉब या कंपनी बदलें, बल्कि आपकी पहली जॉब ही आपको नई ऊचांइयों पर ले जा सकती है, बस जरूरत है कि आप कुछ बातों का खास ध्यान दें। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको फ्रेशर्स के लिए कुछ बेहतरीन कॅरियर टिप्स के बारे में बता रहे हैं-

टीम में काम करना

कॅरियर एक्सपर्ट बताते हैं कि अधिकतर कंपनियां ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहती हैं जो टीम में बेहद अच्छी तरह काम करना जानते हों। ऐसे में अगर आप फ्रेशर हैं और अपने कॅरियर को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको टीम में काम करना आना चाहिए। आपको ऑफिस में कई पर्सनैलिटीज के लोग मिलेंगे, जिनके साथ आपको सहज रूप से काम करना चाहिए। साथ ही किसी भी जिम्मेदारी को उठाना आना चाहिए।

दबाव में काम करना

यह एक ऐसा स्किल है, जो फ्रेशर्स के अंदर कम ही देखने में मिलता है। हालांकि कॅरियर एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप प्रेशर के बीच बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं तो यकीनन अपने कॅरियर में तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। अत्यधिक काम के दबाव में खुद को शांत रखते हुए सही तरीके से काम करने की कला किसी भी कंपनी में उच्चाधिकारियों को इंप्रेस कर सकती हैं।

बेहतर कम्युनिकेशन

यह एक ऐसा कॅरियर टिप्स है, जो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर युवा के लिए जरूरी है। आप अपने काम में चाहें कितना भी माहिर हों, लेकिन अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं है तो आप उसे सबके साथ पेश नहीं कर सकते, जिससे आपको अपने कॅरियर में ग्रोथ नहीं मिलती। इसलिए अपने वर्क स्किल्स के साथ-साथ आपको मौखिक व लिखित कम्युनिकेशन स्किल्स को शॉर्प करने पर भी फोकस करना चाहिए।

अन्य स्किल्स

इनके अलावा भी ऐसी कई बाते हैं जो आपके कॅरियर को प्रभावित कर सकती है। मसलन, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप अपने काम को लेकर कितना फलेक्सिबल हैं या फिर आप अपने वाडरोब पर कितना ध्यान देते हैं। जैसी कई छोटी-छोटी बातें आपके कॅरियर को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। इसलिए इन सभी बातों पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए।

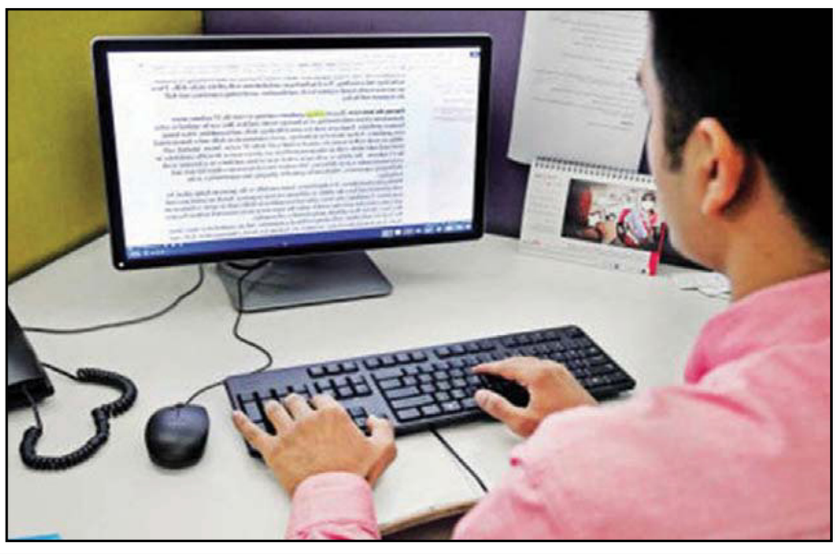

लास एंजिल्स में जस्टिन थॉमस प्रो एम गोल्फ में खेलते हुए।

विराट को तीन टेस्ट मैचों के लिए प्रतिबंधित करें : डेविड लॉयड

लंदन, (एजेंसी)। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर डेविड लॉयड ने कहा है कि दूसरे टेस्ट मैच में अंपायर से बहस के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली को कम से कम तीन टेस्ट मैचों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिये। लॉयड ने कहा कि अगर कोहली किसी औ खेल में ऐसी हरकत करते तो उन्हें सीधे प्रतिबंधित कर दिया जाता। गौरतलब है कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन कोहली की एक फैसले को लेकर मैदानी अंपायर नितिन मेनन से बहस हुई थी। इसके बाद से ही उन पर एक मैच के प्रतिबंध की आशंका व्यक्त की गयी है। लॉयड ने कहा कि मैदान पर इतना कुछ हो जाने के बाद भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कोहली पर कोई शब्द नहीं कहा गया। इससे उन्हें हैरानी हुई है। साथ ही सवाल किया कि एक राष्ट्रीय टीम के कप्तान को मैच अधिकारी की आलोचना करने और डराने की अनुमति है क्या। ऐसा होने के बाद भी उन्हें अगले मैच में खेलने दिया जा रहा है जबकि किसी दूसरे खेल में अगर ऐसा होता तो उन्हें बाहर भेज दिया जाता। उन्हें अहमदाबाद टेस्ट में नहीं खेलने की इजाजत होनी चाहिए।

इंग्लैंड के इस पूर्व खिलाड़ी ने इस मैच में मैच रैफरी जवागल श्रीनाथ के व्यवहार पर भी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रशंसकों को मैदान पर किसी खिलाड़ी के बुरे बर्ताव को दिखाने के लिए येलो और रेड कार्ड की शुरूआत हुई थी। कोहली ने मैदान पर जिस तरह से व्यवहार किया था। उन्हें सीधा रेड कार्ड दिखाना चाहिए था। जिससे वह अगले तीन टेस्ट मैच नहीं खेल पाते। वहीं इस मामले में मैच रैफरी श्रीनाथ ने अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया है।लॉयड से पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी कहा था कि कोहली बड़े खिलाड़ी हैं। वे अंपायर को मैदान पर इस तरह से डरा नहीं सकते। माना कि अंपायर का फैसला ठीक न हो, लेकिन एक कप्तान के तौर पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

आईपीएल के लिए टेस्ट सीरीज छोड़ सकते हैं इंग्लैंड, के क्रिकेटर

मुम्बई, (एजेंसी)। इंग्लैंड के क्रिकेटर आईपीएल के 14 वें सत्र में खेलने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को भी छोड़ सकते हैं। आईपीएल के मुकाबले अप्रैल के दूसरे हफ्ते से शुरू होकर जून तक होंगे। वहीं इस दौरान इंग्लैंड को जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। यह टेस्ट सीरीज 2 जून से शुरू होगी। ऐसे में तैयारी के लिए दोनों टीम के खिलाड़ी कम से कम 10 दिन पहले इंग्लैंड वापस लौट जाएंगे। उसी समय आईपीएल लीग के अंतिम राउंड के मुकाबले चलते रहेंगे। इसके बाद नॉकआउट के भी मुकाबले होंगे। ऐसे में ऑलराउंडर बेन स्टोक्स , तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर के न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने की संभावना नहीं है। यह तीनों ही राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। इसके अलावा क्रिस वोक्स दिल्ली कैपिटल्स से, सैम करेन चेन्नई सुपरकिंग्स से और विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं। ऐसे में ये भी खिलाड़ी प्रभावि होंगे। अगर नॉकआउट में पहुंचने वाली टीम में इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी होता है तो वह खेल सकता है लेकिन जिस खिलाड़ी को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली है उसे फ्रेंचाइजी रिलीज कर देगी जिससे वह टेस्ट टीम में शामिल हो सके। वहीं

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भी संकेत दिए हैं कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ दो जून से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच की तिथियां आईपीएल के नॉकआउट राउंड से टकराती हैं तो वह तब भी अपने खिलाड़ियों को इस टी20 लीग के सभी मैचों में खेलने से नहीं रोकेगा।

सीएसए ने आईसीसी से की ऑस्ट्रेलिया की शिकायत

जोहानिसबर्ग, (एजेंसी)। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) की शिकायत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से की है।

सीएसए ने यह शिकायत कोविड-19 के कारण तीन टेस्ट मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरा स्थगित करने के लिए की है। सीए ने इस महीने की शुरू में ही अपना दक्षिण अफ्रीका दौरा स्थगित कर दिया था। उसने दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के नए मामलों को देखते हुए कहा था कि सेहत सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं इस फैसले से ऑस्ट्रेलिया की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में पहुंचने की राह भी कठिन हो गयी है। सीएसए ने दौरा स्थगित करने के लिए सीए की आलोचना करते हुए कहा था कि यह बेहद निराशाजनक है और इससे उन्हें गंभीर आर्थिक नुकसान होगा। उसने अब आईसीसी के विवाद निवारण विभाग में इसकी शिकायत दर्ज की है।

सीएसए के कार्यवाहक सीईओ फोलेत्सी मोसेकी ने आईसीसी को पत्र लिखकर उससे इस पर गौर करने के लिए कहा है कि डबल्यूटीसी की शर्तों के अनुसार सीए का फैसला स्वीकार्य है या अस्वीकार्य विशेषकर तब जबकि इस श्रृंखला को डब्ल्यूटीसी की 30 अप्रैल 2021 को समाप्त होने वाली समयसीमा तक आयोजित नहीं किया जा सकता है। सीएसए चाहता है कि विश्व क्रिकेट की संचालन संस्था दक्षिण अफ्रीका में स्वास्थ्य स्थिति का आंकलन करके तय करे कि कहीं ऑस्ट्रेलिया ने दौरा स्थगित करके भविष्य के दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) का उल्लंघन तो नहीं किया। आईसीसी की एफटीपी की शर्तों के अनुसार सदस्य देशों को सरकारी निदेर्शों सहित विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होता है।

अमेरिकी कप क्वालीफाईंग के कार्यक्रम में बदलाव

ब्रासीलिया, (एजेंसी)। विश्व बास्केटबॉल की शीर्ष संचालन संस्था (फीबा) ने दो राष्ट्रीय टीमों के तय समय तक नहीं पहुंचने के कारण अमेरिकी कप क्वालीफाईंग के कार्यक्रम में बदलाव किया है। ब्राजील को इस सप्ताहांत कोलंबिया में मैच खेलने थे। फीबा ने कहा कि ब्राजीली टीम को कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के कारण कोलंबिया में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली इस कारण वह नहीं पहुंच पायी। वहीं ब्राजील को इस सप्ताह के अंत में पनामा और पराग्वे से मैच खेलने थे जबकि क्यूबा को प्यूर्टोरिको के सैन जुआन में खेलना था लेकिनक्यूबा की टीम वहां तय समय तक नहीं पहुंच पायी पर इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। क्यूबा को तीन मैच खेलने हैं। इनमें से वह दो मैच कनाडा से और एक डोमिनिका गणराज्य से खेलेगी।

गिरजा/ईएमएस 18फरवरी 2021, (एजेंसी)। विश्व बास्केटबॉल की शीर्ष संचालन संस्था (फीबा) ने दो राष्ट्रीय टीमों के तय समय तक नहीं पहुंचने के कारण अमेरिकी कप क्वालीफाईंग के कार्यक्रम में बदलाव किया है। ब्राजील को इस सप्ताहांत कोलंबिया में मैच खेलने थे। फीबा ने कहा कि ब्राजीली टीम को कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के कारण कोलंबिया में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली इस कारण वह नहीं पहुंच पायी। वहीं ब्राजील को इस सप्ताह के अंत में पनामा और पराग्वे से मैच खेलने थे जबकि क्यूबा को प्यूर्टोरिको के सैन जुआन में खेलना था लेकिनक्यूबा की टीम वहां तय समय तक नहीं पहुंच पायी पर इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। क्यूबा को तीन मैच खेलने हैं। इनमें से वह दो मैच कनाडा से और एक डोमिनिका गणराज्य से खेलेगी।

मेलबोर्न में जापान की नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में खेलती हुई।

सपनों की ताकत को कम न समझें : पांड्या

नई दिल्ली, (संवाददाता)। भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपना एक पुरान वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पांड्या के क्रिकेटर बनने का सफर देखा जा सकता है। इस वीडियो में एक पुराने इंटरव्यू की क्लिप भी है, जिसमें पांड्या एकदम बच्चे नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा भी सपना है कि जिस तरह से ऑलराउंडर इरफान पठान और यूसुफ पठान बड़ौदा और टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं, वैसे ही मैं और क्रुणाल भी बड़ौदा और भारतीय टीम के लिए खेलें।

पांड्या का यह सपना भी समय के साथ पूरा हुआ है। इस वीडियो को शेयर करते हुए हार्दिक ने लिखा, कभी भी अपने सपनों की ताकत को कम मत आंकना। ब्लेस्ड और ग्रेटफुल। आईपीएल ऑक्शन हमेशा मुझे याद दिलाता है कि हम कितना आगे आए हैं। हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी टीम के लिए खेलते हैं। दोनों ही लंबे समय से मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा हैं और टीम को चैंपियन बनाने में इन दोनों का बड़ा हाथ रहा है। हार्दिक ने साल 2015 में मुंबई इंडियंस टीम के लिए अपना पहला आईपीएल मैच खेला था, इसके बाद से वह टीम का अहम हिस्सा बने हुए हैं। हार्दिक ने अभी तक कुल 80 आईपीएल मैच खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 29.97 की औसत और 159.26 के स्ट्राइक रेट से कुल 1349 रन बनाए हैं और कुल 42 विकेट लिए हैं।

स्थानीय तेज गेंदबाजों को मिलेगी जगह : संगकारा

कोलंबो, (एजेंसी)। आईपीएल नीलामी से ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स के निदेशक कुमार संगकारा ने कहा है कि बेहततर गुणवत्ता वाले स्थानीय तेज गेंदबाजों को अधिकांश फ्रेंचाइजियों की सूची में शामिल रहेंगे। संगकारा को आईपीएल के आगामी सत्र 14 के लिए पिछले महीने राजस्थान रॉयल्स के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

संगाकारा ने कहा, यह काफी अच्छा लगता है। यह एक दिलचस्प भूमिका होने जा रही है, एक दिलचस्प चुनौती, कुछ ऐसा जिसे मैंने वास्तव में कुछ समय के लिए नहीं सोचा था, लेकिन जब प्रस्ताव आया, तो मुझे वास्तव में यह समझने में थोड़ा समय लगा कि यह क्या था और फिर, हां बहुत उत्साहित हैं। (घरेलू गेंदबाजों पर) गुणवत्ता वाले स्थानीय पेसर अधिकांश फ्रेंचाइजी की सूची में होंगे।

उन्होंने आगे कहा, वे बहुत मूल्यवान हैं जब आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह उमेश यादव हो या कोई और नया नाम हो सकता है। तेज-गेंदबाज बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए हां, सभी फ्रेंचाइजियों से उन पर ध्यान दिया जाएगा।

वहीं बल्लेबाजों को लेकर इस बारे में कुछ कहना कठिन है। । हमारे पास वे रिक्तियां हैं जिन्हें हम भरने की कोशिश करेंगे। टीमें बेहतर खिलाड़ियों को अवसर जरुर देंगी।

700 रेटिंग अंकों से आगे निकलने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने ऋषभ

चेन्नई, (एजेंसी)। भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ताजा विश्व रैंकिंग में 11वें स्थान के साथ ही 715 रेटिंग अंकों के साथ ही एक अहम रिकार्ड अपने नाम किया है। ऋषभ पहले भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने 700 रेटिंग अंकों का आंकड़ा पार किया है। यहां तक कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक 662 तक ही पहुंचे थे। उनके अलावा दिग्गज विकेटकीपर रहे फारूख इंजीनियर के भी 619 अंक ही थे। धोनी की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 19वां स्थान थी। साल 1973 में फारूख इंजीनियर भी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 17वें स्थान तक ही पहुंचे थे। ऋषभ ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही शानदार फॉर्म में बने हुए हैं। सिडनी टेस्ट में इस युवा बल्लेबाज ने दूसरी पारी में 87 रन बनाकर भारतीय टीम को हार से बचाया था। वहीं ब्रिसबेन टेस्ट में ऋषभ की नाबाद 89 रनों की पारी की सहायता से ही भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में सफल रही। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट में भी ऋषभ ने 91 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 77 गेंदों पर नाबाद 58 रन बनाए थे।

वहीं आर अश्विन इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के कारण ऑलराउंडरों की सूची में पांचवें स्थान पर पहुंच गये हैं। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में दूसरे टेस्ट मैच में भारत की दूसरी पारी में 106 बनाये और मैच में आठ विकेट लिये। वहीं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजों में पांचवें स्थान पर बने हुए हैं। इसके अलावा दूसरे टेस्ट में 161 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा नौ स्थानों की छलांग लगाते 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑलराउंडरों की सूची में अश्विन के 336 अंक हैं।

रसेल जैसे स्टार खिलाड़ी साबित होंगे जेमीसन

नई दिल्ली, (संवाददाता)। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के काइल जेमीसन की तारीफ करते हुए कहा है कि वह अगले आंद्रे रसेल बनेंगे। गंभीर ने कहा, जेमीसन इस समय कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन वह स्टार साबित हो सकते हैं। वह सात फीट लंबे हैं. 140 की स्पीड पर गेंदबाजी करते हैं। वह अगले आंद्रे रसेल साबित हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हां, वह पूरी तरह तैयार खिलाड़ी हैं।

काइल जेमीसन ने फरवरी 2020 में भारत के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से छह टेस्ट और 4 टी20 खेले हैं। भारत के खिलाफ डेब्यू में उन्होंने 39 रन देकर चार विकेट लिए थे। इनमें चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी के बड़े विकेट शामिल थे। इस दौरान उन्होंने 44 रन की पारी भी खेली थी। पाकिस्तान के खिलाफ जेमीसन ने एक टेस्ट में 11 विकेट लिए थे। तीनों फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा है। न्यूजीलैंड घरेलू क्रिकेट में नई गेंद से विकेट लेने की क्षमता वह दिखा चुके हैं। उनके पास बड़े हिट लगाने की क्षमता है। नंबर 6 या 7 पर वह बल्ले से करिश्मा कर सकते हैं। वह किसी भी टीम की ताकत हो सकते हैं।

गंभीर ने कहा, रसेल और क्रिस मौरिस पहले ही ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं लेकिन काइल जेमीसन लगातार बेहतर होंगे। उनका भारत में पहला अनुभव होगा। यहां से वह बेहतर होना शुरू करेंगे। आईपीएल 2021 का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि यह टूनार्मेंट अप्रैल से मई के बीच खेला जाएगा।

लीवरपूल में इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी के रियाद मेहरेज अपना दूसरा गोल करते हुए।

नासिर हुसैन ने इंग्लैंड के स्पिन विभाग में निरंतरता के अभाव को बताया सबसे बड़ी कमी

लंदन, (एजेंसी)। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन का मानना है कि जो रूट की अगुवाई वाली टीम को अगर बाकी बचे दो टेस्ट मैचों में अनुकूल परिणाम हासिल करना है तो उसे भारतीय पिचों की स्थिति का रोना रोने के बजाय अपने स्पिन विभाग के निरंतरता के अभाव को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। हुसैन ने कहा कि डॉम बेस का लेंथ को बरकरार नहीं रख पाना इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत ने मंगलवार को दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 317 रन से करारी शिकस्त देकर चार मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की। नासिर हुसैन ने अपने कॉलम में लिखा, इंग्लैंड को पिच, टॉस, डीआरएस, अंपायर या इस तरह की किसी भी चीज का रोना रोने के बजाय उन विभागों में सुधार करना चाहिए जिनमें वह कमतर नजर आया। मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा, भले ही उन्हें विकेट मिलते रहे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा स्पिन विभाग में निरंतरता का अभाव रहा। यह केवल इस टेस्ट मैच की बात नहीं है। श्रीलंका दौरे पर ध्यान दो तो जैक लीच और डॉम बेस ने विकेट लिए लेकिन विशेषकर बेस की लेंथ में निरंतरता का अभाव रहा।

हुसैन ने कहा कि भारतीय स्पिनरों ने इंग्लैंड के स्पिनरों की तुलना में बेहतर गेंदबाजी की तथा अनुभवी मोईन अली का भी अपनी गेंदों पर नियंत्रण नहीं था हालांकि वह 2019 में एशेज के बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अली ने आठ विकेट (दूसरे टेस्ट में) लिए और उसने कुछ बेहतरीन गेंद की जैसे कि वह गेंद जिस पर उसने पहली पारी में विराट कोहली का विकेट लिया और उन्हें मैच में दो बार आउट किया, लेकिन मोईन ने स्वयं स्वीकार किया कि पहली पारी में उनका अपनी गेंदों पर पर्याप्त नियंत्रण था तथा आप स्पिनरों के लिए मददगार पिच पर 128 पर चार विकेट का प्रदर्शन नहीं चाहते थे। हुसैन ने कहा, अगर आप तुलना करो तो भारत के दो स्पिनरों ने कैसे गेंदबाजी तो उन्होंने कुछ जादुई नहीं किया बल्कि उनका अपनी गेंदों पर नियंत्रण रखा। अगर आप मुझसे इंग्लैंड की हार का मुख्य कारण पूछोगे तो मैं कहूंगा कि देखिये भारत के दो स्पिनरों रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल ने कैसी गेंदबाजी की। इंग्लैंड के स्पिनरों की तुलना में उन्होंने अधिक निरंतरता दिखाई।

ओलंपिक क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों की संख्या घटेगी

नई दिल्ली, (संवाददाता)। आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिये मुक्केबाजी के वैश्विक क्वालीफिकेशन टूनार्मेंटों के रद्द होने से इन खेलों में भारत के लिए कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने की संभावनाएं घटी हैं। मुक्केबाजों को जून में पेरिस में एक टूनार्मेंट खेलना था जिससे 53 कोटा स्थानों का निर्धारण होना था।

वहीं अब ये स्थान साल 2017 से विश्व रैंकिंग के आधार पर उपमहाद्वीपों में बराबर बांटे जाएंगे।भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले साल एशियाई क्वालीफायर्स से ये कोटा हासिल किया था। इस टूनार्मेंट के बाद कोविड-19 के कारण वैश्विक प्रतियोगिताएं रूक गई थी। रैंकिंग में जो खिलाड़ी बेहतर स्थिति में उन्होंने ही ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है। अमित पंघाल अपने भार वर्ग में शीर्ष पर है। जिन भार वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों की जगह पक्की नहीं है उनमें पुरुषों में 57 किग्रा, 81 किग्रा और 91 किग्रा के साथ महिलाओं में 57 किग्रा है। भारतीय मुक्केबाजी के हाई परफोरमेंस निदेशक सैंटियागो नीवा को हालांकि उम्मीद है कि कुछ और खिलाड़ी क्वालीफिकेशन हासिल कर सकते है। उन्होंने कहा कि जाहिर है हम इससे निराशा है लेकिन हम अभी भी आशान्वित हैं।

हम आईओसी के कदम का इंतजार करते है। मुझे वास्तव में खुशी है कि एशियाई क्वालीफायर में हमारा प्रदर्शन अच्छा था, यह उन खिलाड़ियों के लिए झटका है जो वहां कोटा नहीं हासिल कर सका।